RIN No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : भोपाल/म.प्र./581/2021-2023
Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

वर्ष 22 अंक 02 05 अक्टूबर 2021

जगत विज़न

कमल vs कमलनाथ

सत्ता का सेमीफाईनल

साबित होंगे उपचुनावों के नतीजे

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 22 अंक 02 05 अक्टूबर 2021

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
राजनीतिक संवाददाता	समीर शास्त्री
विशेष संवाददाता	बिन्देश्वरी पटेल
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
छत्तीसगढ़ संवाददाता	आनन्द मोहन श्रीवास्तव,
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
गोवा ब्यूरो चीफ	अजय सिंह
गुजरात ब्यूरो चीफ	गौरव सेठी
दिल्ली ब्यूरो चीफ	विजय वर्मा
पटना संवाददाता	सौरभ कुमार
उत्तरप्रदेश ब्यूरो चीफ	वेद कुमार
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान
विधिक सलाहकार	एडवोकेट राजेश कुंसारिया

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.in

(पृष्ठ क्र.-6)

- कांग्रेस हाईकमान को छत्तीसगढ़ संभालना बड़ी चुनौती 24
- प्रकृति, आदिवासी बिरहोर ओर झारखंड 28
- सख्त कानूनों से भी नहीं घट रहे बलात्कार के मामले 30
- दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर उठते सवाल 34
- मंथन से निकला बक्सवाहा जंगल बचाने का अमृत 38
- ममता बनर्जी की निगाहें भवानीपुर उपचुनाव में जीत के 41
- पर्यावरण सुरक्षा को बनायें नागरिक धर्म 44
- वैक्सीन की प्रथम डोज आंशिक सुरक्षा, दूसरी डोज 46
- संकल्प के साथ जिंदगी जी रहे वृक्षमित्र सुनील दुबे 48
- मनुष्य की प्रवृत्ति और पलायनवादिता 50
- कितना दुरूह है मरूस्थल का जीवन 52
- प्रदूषण का शिकार सारा जगत 54
- जिन्हें ताज मिला मगर कब्र नहीं 56
- 30-30 Is Better Option Than 20-20...... 62
- Peacemaker Hero Mohandas K. Gandhi 64

कार्टूनिस्ट की नज़र में भूपेश सरकार

संपादकीय

वर्ष 2022-23

देश में चुनाव पर्व

देश में 2023 का साल चुनावों के लिए रिजर्व होगा। एक अंतराल के बाद पूरे साल भर देश के विभिन्न राज्यों में आमचुनाव होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव तक देश में चुनावी त्योहारों का लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा और हर 06 महीने में चुनावी पर्व दस्तक देता रहेगा। इस दौरान करीब 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। इसके बाद आम चुनाव की तैयारी शुरू होगी। फरवरी-मार्च 2022 में पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा के चुनाव होंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा चार राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। इन पांच सूबों के चुनाव के छः-सात महीने बाद ही नवंबर-दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इन दोनों सूबों में भी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है। चुनावी मौसम की यह फिजां 2023 की शुरूआत में भी जारी रहेगी। पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मेघालय, नगालैंड और त्रिपुरा में मार्च 2023 में विधानसभा की अवधि पूरी हो रही है और वहां चुनाव होंगे। वहीं इसके दो महीने बाद ही मई में कर्नाटक का चुनाव होगा। राज्यों के चुनावी उत्सव का यह दिसंबर 2023 में अपने चरम पर पहुंचेगा जब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान और तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होंगे। इन राज्यों का चुनाव एक तरह से आम चुनाव का सेमीफाइनल होगा। चुनावी पर्व का समापन अप्रैल-मई 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ होगा।

निश्चित तौर पर इन चुनावों के कारण सरकारों का पूरा ध्यान चुनावों पर रहेगा और सरकारों के अन्य काम बाधित होते रहेंगे। देश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब इतने बड़ी संख्या में चुनाव होंगे। यह हमारे देश की विडंबना ही है कि साल भर कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। आम चुनाव तो होते ही है। उपचुनाव भी बड़ी संख्या में होते हैं। इन चुनावों का विशेष फर्क सरकार के काम काज पर पड़ता है। चुनावों की घोषणा के बाद ही उस क्षेत्र विशेष में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। मतलब सरकार की ओर से किये जाने वाले सभी विकासीय कार्यो में बाधा आना। जिसका असर कहीं न कहीं हमारे ऊपर ही पड़ता है। बड़ा दिलचस्प है कि शासन के विभिन्न स्तर पर कार्यो को टाला जाता है लेकिन जब बात चुनावों की होती है यह समय पर ही कराये जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाती है। जबकि ऐसे कई अवसर आए है जब आमजन से जुड़े कार्यो को टाला गया है।

विजया पाठक

कमल Vs कमलनाथ

सत्ता का सेमीफाईनल साबित होंगे उपचुनावों के नतीजे

मध्यप्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनावों की तारीख आ गई हैं। आगामी 30 अक्टूबर को इन सीटों पर चुनाव होंगे। इसके साथ ही दमोह उपचुनाव के बाद एक बार फिर से कांग्रेस-बीजेपी फिर आमने-सामने की लड़ाई में होंगे। राज्य में खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। यह उपचुनाव काफी अहम होने वाले हैं। दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस खुश है और बीजेपी इस हार से उबरकर एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। चार में से दो सीटों पर बीजेपी और दो पर ही कांग्रेस का कब्जा रहा था। उपचुनाव में चारों ही सीटें जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। यह भी सच है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में केन्द्र में आदिवासी रहेंगे। मतलब साफ है कि उपचुनाव के नतीजे भी पूरी तरह से आदिवासी वोटों पर निर्भर हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए अभी दो साल हैं। लेकिन पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में हुए नुकसान का खामियाजा भाजपा को अपनी पंद्रह साल पुरानी सरकार को गंवाकर भुगतान पड़ सकता है। राज्य में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2023 में हैं। इससे पहले पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जाना है। उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दल कांग्रेस फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने के मूड में हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है, कांग्रेस ने जिस प्लान के साथ दमोह उपचुनाव जीता था, उसी प्लान के तहत प्रदेश में होने वाले चारों उपचुनाव भी पार्टी जीत जाएगी। कमलनाथ उपचुनाव से संबंधित क्षेत्रों के पदाधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दे चुके हैं। दरअसल, मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दमोह उपचुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था इसलिए कमलनाथ ने चुनाव के सारे सूत्र अपने हाथ में रखे। प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ स्तर की रणनीति को अपनी देखरेख में अंजाम दिया। भरोसे के विधायकों की तैनाती की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ रोड शो भी किया। भाजपा नेतृत्व अपनी चुनावी रणनीति में सामाजिक समीकरणों पर काफी जोर दे रहा है। पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को अमली-जामा पहना रही है। यह भी सच है कि शिवराज सरकार का आदिवासियों के प्रति बड़ते रूझान के पीछे प्रदेश कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आदिवासियों को लेकर जो मुद्ददे या मसले उठाये जा रहे हैं उससे मध्यप्रदेश सरकार मजबूरन आदिवासियों के हितों के प्रति फिक्रमंद दिख रही है। साथ ही इस समय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। आदिवासी वोटर विधानसभा की 90 सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर हुई है। इसकी बड़ी वजह आदिवासी वोटों का विभाजन रहा है। मध्यप्रदेश में वैसे तो आदिवासियों की आबादी 22 फीसदी है और ये विधानसभा की 95 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन अभी मध्यप्रदेश में चार सीटों पर उपचुनाव होना है।

बीजेपी-कांग्रेस लगा रही ऐड़ी-चोटी का जोर

विजया पाठक

दमोह उपचुनाव के बाद एक बार फिर से कांग्रेस-बीजेपी फिर आमने-सामने की लड़ाई में होंगे। राज्य में खंडवा लोकसभा के अलावा पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। यह उपचुनाव काफी अहम होने वाले हैं। दमोह उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस खुश नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस हार से उबरकर एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट जीतने के लिए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ लगातार पार्टी बैठकें कर रहे हैं वहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी क्षेत्रों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। खास बात ये है कि चार में से दो सीटों पर बीजेपी और दो पर ही कांग्रेस का कब्जा रहा था। वहीं आने वाले चुनाव में चारों ही सीटें जीतने के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। एक ओर जहां कांग्रेस सहानुभूति से चुनाव जीतने का प्लान बना

कमलनाथ की रणनीति से दमोह उपचुनाव जीता भाजपा में उभरे थे विरोधी सुर

दमोह विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे राहुल लोधी भले ही भाजपा के हो गए हों लेकिन उपचुनाव के परिणाम के बाद दमोह कांग्रेस का ही रहा। इस उपचुनाव को जीतने की रणनीति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ही तैयार की और इसका सफल क्रियान्वयन किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की रणनीति से दमोह विधानसभा सीट कांग्रेस के पास ही रही। कमलनाथ का सबसे बड़ा दांव जनादेश के अपमान करने को लेकर था और वे मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचाने में सफल रहे कि राहुल लोधी ने उनके पिछले फैसले को नजरअंदाज किया था। इस जीत से कांग्रेस को संजीवनी मिली थी। उधर केंद्रीय मंत्री व दमोह से सांसद प्रह्लाद पटेल और गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा में षड़यंत्र व भितरघात की बात उठाई थी। कांग्रेस से भाजपा में आए और भाजपा की टिकट पर उपचुनाव लड़े प्रत्याशी राहुल सिंह भाजपा के स्थानीय वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जयंत मलैया और उनके परिवार पर पहले ही आरोप लगा चुके थे। इस उपचुनाव को जीतने की रणनीति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ही तैयार की थी और इसका सफल क्रियान्वयन किया। अब उनकी तैयारी अगले विधानसभा चुनाव को लेकर है। दरअसल, मध्यप्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद दमोह उपचुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था इसलिए कमलनाथ ने चुनाव के सारे सूत्र अपने हाथ में रखे। प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ स्तर की रणनीति को अपनी देखरेख में अंजाम दिया। भरोसे के विधायकों की तैनाती की। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ

रही है, वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अब बची ही कहां है? राज्य में भाजपा को दोबारा सत्ता में लौटे हुए लगभग 15 माह का वक्त गुजर गया है। इस दौरान संगठन के सामने कई उतार-चढ़ाव भी आए, 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में बीजेपी 19 स्थानों पर जीतने में सफल रही थी तो वहीं कांग्रेस ने नौ स्थानों पर बाजी मारी थी। उसके बाद दमोह विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, इस हार को भाजपा ने गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि

राज्य में भाजपा को दोबारा सत्ता में लौटे हुए लगभग 15 माह का वक्त गुजर गया है। इस दौरान संगठन के सामने कई उतार-चढ़ाव भी आए, 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव में बीजेपी 19 स्थानों पर जीतने में सफल रही थी तो वहीं कांग्रेस ने नौ स्थानों पर बाजी मारी थी।

संगठन की मजबूती के लिए लगातार कोशिशों का दौर जारी है। यह भी सच है कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में केन्द्र में आदिवासी रहेंगे। मतलब साफ है कि उपचुनाव के नतीजे भी पूरी तरह से आदिवासी वोटों पर निर्भर हैं। मध्यप्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लिए अभी दो साल हैं। लेकिन पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में हुए नुकसान का खामियाजा भाजपा को अपनी पंद्रह साल पुरानी सरकार को गंवाकर भुगतान पड़ सकता है। अगले चुनाव में सत्ता

प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गए हैं उपचुनाव

गंवाने का खतरा उठाने की स्थिति में पार्टी नहीं है। राज्य में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2023 में हैं। इससे पहले पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी जाना है। उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विरोधी दल कांग्रेस फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने के मूड में हैं। यही कारण है कि दोनों पार्टियां जमीनी स्तर से रिपोर्ट मंगा रही हैं। दोनों राजनीतिक दलों के लिए इसकी वजह भी है क्योंकि कोरोना का संकट आया, महंगाई लगातार बढ़ रही है और किसान आंदोलन भी चल रहे हैं। कांग्रेस जहां इन समस्याओं को मुददा बनाकर चुनाव जीतना चाहती है, वहीं भाजपा की कोशिश है कि इन मुददों को ज्यादा तूल नहीं दिया जाए। इसके लिए वह रणनीति बना रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है, कांग्रेस ने जिस प्लान के साथ दमोह उपचुनाव जीता था, उसी प्लान के तहत प्रदेश में होने वाले चारों उपचुनाव भी पार्टी जीत जाएगी। कमलनाथ उपचुनाव से संबंधित क्षेत्रों के पदाधिकारियों को एक्टिव रहने के निर्देश दे

उपचुनाव में केन्द्र बिंदु में आदिवासी

चुके हैं।

खंडवा लोकसभा से भाजपा के नंदकुमार सिंह चैहान सांसद हुआ करते थे। पृथ्वीपुर सीट से कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर व जोबट सीट से कलावती भूरिया और रैगांव सीट से भाजपा के जुगल किशोर बागरी विधायक थे। अब इन सीटों पर वापसी के लिए दोनों ही दल इस उपचुनाव को जीतने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। भाजपा और कांग्रेस इन उप चुनावों में जीत के लिए हर संभव जोर लगाने की तैयारी में है। भाजपा की कार्यसमिति की बैठक पिछले दिनों भोपाल में हो चुकी है और इस बैठक में भी नेताओं के बीच उपचुनाव पर चर्चा हुई है। कांगेस खण्डवा सहित सभी विधानसभा सीटों पर उतरने वाले उम्मीदवारों की घोषाणा कर चुकी है।

राजनीतिक विष्लेषकों का मानना है कि दमोह में हुए विधानसभा के उपचुनाव में मिली हार ने भाजपा को हालात से परिचित करा दिया है, तो वहीं कांग्रेस को संभावनाएं नजर आने लगी हैं। यही कारण है कि दोनों

उपचुनाव को लेकर एक्टिव हुई सरकार

सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बुरहानपुर का दौरा कर चुके हैं। चुनाव के मद्देनजर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को निवाड़ी का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। खण्डवा लोकसभा सीट चार जिलों तक फैली है, जिसमें अलोक शर्मा को बुरहानपुर, खण्डवा जिले में कविता पाटीदार, देवास जिले में पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय और खरगोन जिले में जीतू जिराती को ज़िम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा खंडवा लोकसभा सीट में आने वाली विधानसभा सीटों में से हर सीट पर एक कैबिनेट मंत्री को प्रभार दिया गया है। खंडवा लोकसभा सीट के नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री तुलसी सिलवाट, बुरहानुपर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार, मांधाता विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विजय शाह, खण्डवा विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री कमल पटेल, पंधाना विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री मोहन यादव, बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री उषा ठाकुर, भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र और बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री जगदीश देवड़ा को ज़िम्मेदारी दी गई है। लोकसभा उपचुनाव के साथ ही विधानसभा उपचुनावों के लिए भी भाजपा ने कमर कस ली है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री रामखिलावन पटेल, बिसाहूलाल सिंह और बृजेन्द्र प्रताप सिंह, अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र के लिए मंत्री विश्वास सारंग, प्रेम सिंह पटेल को ज़िम्मेदारी दी गई है।

दल उपचुनाव को पूरे जोर और दमखम से लड़ेंगे। इतना ही नहीं इन उपचुनावों के नतीजों का असर आगामी नगरीय निकाय व पंचायतों के चुनाव पर तो होगा ही, साथ में लोकसभा व विधानसभा के चुनाव तक असर छोड़े तो बड़ी बात नहीं होगी।

कहां कौन सी सीट है खाली- दरअसल खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह लोकसभा सीट खाली चल

आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संदेश होंगे उपचुनाव

दमोह की तर्ज पर कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ेंगे उपचुनाव- कमलनाथ

कमलनाथ ने कहा कि दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की बड़े अंतर से जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम थी। चुनाव मतदान केंद्र और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ लड़ा था। हमारा मुकाबला भाजपा नेताओं से नहीं बल्कि उनके संगठन से है। अब बड़ी-बड़ी सभा, रैली की जगह जनता से सीधे जुड़ाव का समय है। जिसने यह कर लिया, उसकी जीत पक्की है। इसके लिए मंडल और सेक्टर की इकाइयों में योग्य व निष्ठावान लोगों का चयन करें। इसमें तेरा-मेरा नहीं होना चाहिए। अपनी 15 माह की सरकार के कामकाज का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी कांग्रेसजन का सिर शर्म से झुकने नहीं दिया। आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था के क्या हाल हैं, सबको पता हैं। उपचुनाव के परिणाम युवा, किसान और प्रदेश के लोगों के आत्मसम्मान का भविष्य तय करेंगे।

दमोह प्लान पर कांग्रेस को भरोसा

कांग्रेस आगामी उपचुनाव में भी दमोह उपचुनाव की रणनीति के तहत ही उतरेगी। इसके लिए पार्टी उपचुनाव वाली हर सीट पर कम से कम 10 विधायकों को तैनात करेगी, ताकि वह पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकें। बता दें कि दमोह उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटखनी दे दी थी। दमोह उपचुनाव के बाद से पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। कांग्रेस उपचुनाव में युवा मतदाताओं पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस विधायकों के साथ ही अपनी छात्र शाखा एनएसयूआई के ढेरों कार्यकर्ताओं को भी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है। साथ ही कई युवा विधायकों को उपचुनाव में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है।

रही है। कोरोनाकाल संकट के दौरान निर्वाचन आयोग ने खंडवा लोकसभा का उपचुनाव टाल दिया था, लेकिन इसके बाद राज्य में कोरोना वायरस के कारण निवाड़ी से कांग्रेस विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह, जोबट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया और रैगांव

विधानसभा की 03 सीटें कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठापूर्ण

भाजपा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा बुरहानपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण यादव का नाम निश्चित माना जा रहा है इसलिए यह सीट कमलनाथ के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत यादा परेशानी वाली नहीं है लेकिन टीकमगढ़ जिले की पृथ्वीपुर और झाबुआ जिले की जोबट विधानसभा सीट कमलनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है क्योंकि दोनों सीट कांग्रेस के पास थीं। यदि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है तो इसे कमलनाथ का मिस मैनेजमेंट और लोकप्रियता का गिरता हुआ ग्राफ बताया जाएगा। रैगांव सीट भाजपा के पास थी परंतु यदि कमलनाथ इस सीट पर जीतने में कामयाब होते हैं तो यह उनके लिए बड़ी सफलता होगी। इससे पार्टी में नया उत्साह का संचार होगा। पृथ्वीपुर सीट पर कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के कोरोना के कारण निधन के कारण खाली हुई है। जोबट सीट पर कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन से खाली हुई है। रैगांव सीट भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई है।

से बीजेपी विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन हो गया। अब लोकसभा के साथ इन तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जहां अपनी जमीन को और पुख्ता करने पर जोर है तो वहीं कांग्रेस की कमजोर कड़ी पर भी उसकी पैनी नजर है। यही कारण है कि संगठन लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय

जानते है लोस और विस सीटों के बारे में

जोबट (अलीराजपुर)

आदिवासी बहुल इस सीट की विधायक कलावती भूरिया का निधन 24 अप्रेल को हुआ। उन्होंने भाजपा के माधोसिंह डावर को परास्त किया। 2018 में कांग्रेस के बागी विशाल रावत ने कांग्रेस के वोटों में लंबी सेंध लगाई, फिर भी भाजपा जीत नहीं पाई। कांग्रेस अब कांतिलाल भूरिया के भरोसे है। इधर, अब कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री सुलोचना रावत और उनके पुत्र विशाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। सुलोचना को भूरिया खेमे का विरोधी माना जाता है। 2018 के चुनाव में सुलोचना ने कलावती को टिकट देने का विरोध किया था। उनके पुत्र विशाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे।

खंडवा लोकसभा सीट

छह बार के सांसद नंदकुमार सिंह चौहान का इसी वर्ष मार्च में कोरोना से निधन हो गया। इस सीट पर अब तक हुए 07 बार भाजपा, 09 बार कांग्रेस को जीत मिली। इस सीट पर दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। वर्ष 1977 में लोकदल पार्टी के परमानंद ठाकुर दास जीते। असामायिक निधन पर 1979 में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे जीते।

पृथ्वीपुर (निवाड़ी)

वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर काबिज रहे बृजेंद्र सिंह राठौर का 2 मई को निधन हुआ था। कांग्रेस ने उनके बेटे नितेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 2008 में बृजेंद्र ने भाजपा प्रत्याशी सुनील नायक को हराया था। हालांकि मतदान के दिन ही नायक पर फायरिंग हुई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई। तब बृजेंद्र सिंह राठौर और उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ था। वर्ष 2013 में सुनील नायक की पत्नी अनिता ने बृजेंद्र सिंह को हरा दिया। भाजपा ने 2018 में अभय प्रताप सिंह को टिकट दिया, जो चौथे नंबर की पार्टी रही।

रैगांव (सतना)

अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट भाजपा नेता जुगुल किशोर बागरी की परंपरागत सीट रही है। 10 मई को उनके निधन के बाद मैदान खाली है। 2008 में घोटाले का दाग लगने पर 2013 में टिकट कट गया था। तब बेटे पुष्पराज को बसपा की ऊषा चौधरी ने हरा दिया। 2018 में जुगुल ने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को परास्त किया। ऊषा चौधरी अब कांग्रेस में हैं। कल्पना भी ताल ठोंक रही हैं। भाजपा जुगुल के परिवार से ही किसी को टिकट दे सकती है।

रहने के मंत्र दे रहा है, तो कांग्रेस के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है जो भाजपा में आने को तैयार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा हर मोर्चे पर सक्रियता से काम करने में भरोसा करती है। हर समय वह चुनाव के मूड में रहती है और संगठन लगातार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सयि बनाए रखने का काम करता है।

शिवराज का भविष्य तय करेंगे उपचुनाव के नतीजे

चार उपचुनाव को लेकर शिव–विष्णु की जोड़ी अपने सहयोगियों के साथ मैदान में मोर्चा खोल चुकी है। उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। भाजपा ने इस चुनौती को गंभीरता से लेकर जमावट तेज कर दी थी। 28 विधानसभा उपचुनाव में जरूरी जीत हासिल कर शिवराज और महाराज की जोड़ी ने भाजपा की सत्ता को मजबूती दी थी। क्या तीन विधानसभा और एक लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद भाजपा मिशन 2023 विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर पाएगी। वक्त का तकाजा है कि दमोह विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद इन 4 उपचुनाव के लिए भाजपा एकजुट नजर आए। जो भाजपा में जारी भ्रम के कारण संभव नहीं हो पा रहा। भाजपा यदि आज चर्चा में है तो वजह है सीएम इन वेटिंग के दावेदारों में उलझकर रह जाने के कारण। अगला मुख्यमंत्री भी पिछड़े वर्ग का होगा तो नई पीढ़ी में ऐसा कौन नेता जो सबको साथ लेकर चल सके या फिर केंद्रीय नेतृत्व की मंशा और अपेक्षा के अनुरूप ही कोई नया प्रयोग मध्यप्रदेश में किया जाएगा। मंत्री हो या विधायक, सांसद हो या केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय पदाधिकारी ज्यादातर भी इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर बीजेपी किस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है।

कोरोनाकाल में यह दिखा भी कि पार्टी संगठन ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश की तो वहीं कोरोना टीकाकरण में पार्टी अपनी भूमिका को निभा रही है, तो वहीं विरोधी दल को कमजोर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कुल मिलाकर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस है और उसे वह हर स्तर पर कमजोर करने में लगी है। यह नजर भी आता है। इन स्थितियों में कांग्रेस को अपने को मजबूत बनाए रखना किसी चुनौती से कम भी नहीं है।

उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले अभी न हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने उपचुनाव वाली सीटों पर जोर आजमाइश शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने खंडवा लोकसभा सीट के लिए लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है।

बीजेपी उम्मीदवार पर लग रहीं अटकलें

दूसरी ओर अब तक खंडवा लोकसभा सीट को लेकर रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा खंडवा लोकसभा सीट के करीब से गुजरी तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वहां पहुंचकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। वीडी शर्मा ने यहां कुशाभाऊ

जयस ने बढ़ायी बीजेपी-कांग्रेस की टेंशन

खंडवा और जोबट सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी

जोबट-खंडवा दोनों पर आदिवासी वोट बैंक खासा असर रखते हैं। जोबट-खंडवा दोनों पर आदिवासी वोट बैंक खासा असर रखते हैं। दमोह सीट पर उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है हालांकि जयस ने उसकी खुशी में थोड़ा खलल जरूर डाल दिया है। उपचुनाव से पहले जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानि जयस फिर सक्रिय है। उसकी सक्रियता ने कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर बल ला दिया है। चुनाव 4 सीटों पर है उनमें से मालवा में आने वाली दो सीट्स पर जयस अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उपचुनाव में जयस एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढा रहा है। खासतौर से खंडवा लोकसभा और जोबट विधानसभा सीट पर जय आदिवासी युवा संगठन सक्रिय हो गया है। वो दोनो सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। इन दोनों सीट पर आदिवासी वोटर निर्णायक साबित होते हैं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रहीं है। हाल ही में महू में जयस के प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से निलंबित किए गए पटवारी नीतेश अलावा को जोबट सीट पर चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के विधायक और जयस को खड़ा करने वाले हीरालाल अलावा का कहना है खंडवा और जोबट उपचुनाव जय आदिवासी युवा संगठन पूरी ताकत से लड़ेगा। इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि कांग्रेस यदि युवा आदिवासी को मौका देती है तो मिलकर चुनाव लड़ने पर भी विचार किया जा सकता है।

बीजेपी पर भी पड़ेगा असर- खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी के नंदकुमार सिंह चौहान के कोरोना से निधन के कारण खाली हुई है। जोबट विधानसभा सीट कांग्रेस की विधायक कलावती भूरिया के कोरोना के कारण निधन से खाली हुई है। बीजेपी इन दोनों सीटों पर फतह के लिए अपनी अलग रणनीति बना रही है। अभी हाल ही में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। वो योग्य उम्मीदवारों की तलाश में है, लेकिन जयस, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए चुनौती बनी हुई है।

जयस ने बदले समीकरण- दमोह सीट पर उपचुनाव में मिली जीत से कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि जयस ने उसकी खुशी में थोड़ा खलल जरूर डाल दिया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल का कहना है कांग्रेस खंडवा और जोबट समेत सभी चारों उपचुनाव जीतेगी। आदिवासी भी कांग्रेस के साथ हैं। कोरोना और महंगाई के कारण लोग खासे परेशान हैं। इसलिए वे कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का मन बना चुके हैं। जिस तरह जयस का युवा नेतृत्व मैदान में उतर गया है, उसे देखकर लग रहा है कि खंडवा हो या जोबट उपचुनाव, कोई भी पार्टी आदिवासी युवाओं को नजरअंदाज करने की हालत में नही है। इसीलिए कांग्रेस खंडवा से किसी आदिवासी युवा चेहरे को उतारने की रणनीति पर काम कर रही है।

ठाकरे के नाम पर सहानुभूति के वोट बटोरने का अभियान शुरू किया है। दरअसल खंडवा सीट पर कुशाभाऊ ठाकरे चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में बीजेपी ठाकरे के नाम पर लोगों के बीच सहानुभूति बनाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि बीजेपी के संभावित

उम्मीदवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खंडवा सीट पर दावेदारी कर रही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को पार्टी ने प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा माना जा रहा है कि खंडवा सीट पर बीजेपी पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के बेटे को अपना उम्मीदवार बना सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी वीडी शर्मा का कहना है कि खंडवा लोकसभा सीट उपचुनाव होने वाला है। संगठन का विस्तार महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं और कार्यकर्ताओं के बूते पर पार्टी चुनाव जीतेगी। फिलहाल पार्टी के नेताओं ने ही खंडवा सीट पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी संभाल रखी है। उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है क्योंकि इस सीट पर हार-जीत राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा संदेश देगी। यही कारण है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवार के चेहरे के सहारे और बीजेपी ने बिना उम्मीदवार के पार्टी नेताओं के चेहरे आगे रख उपचुनाव में प्रचार का बिगुल बजाना शुरू कर दिया है।

पृथ्वीपुर सीट पर नजर

पृथ्वीपुर विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन से रिक्त हुई है। राठौर कद्दावर नेता थे और अपने जनाधार के बल पर दो बार निर्दलीय विधायक भी बने। उनके निधन से लोगों की सहानुभूति राठौर परिवार के प्रति है। यहां से संभावित कांग्रेस प्रत्याशी उनके बेटे नीतेंद्र सिंह राठौर हैं। भाजपा के पास इस सीट से मजबूत प्रत्याशी नहीं है। पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी से आए नेता को भाजपा उम्मीदवार बनाया गया था।

आदिवासियों पर बीजेपी की नजर उपचुनावों में गेम चेंबर साबित होंगे आदिवासी वोट

भाजपा नेतृत्व अपनी चुनावी रणनीति में सामाजिक समीकरणों पर काफी जोर दे रहा है। पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदायों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति को अमली-जामा पहना रही है। गुजरात में सरकार में हुए संपूर्ण बदलाव में सबसे ज्यादा महत्व इन्हीं वर्गो को दिया गया है। अन्य रायों में भी पार्टी इसी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। पार्टी विभिन्न राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। गुजरात में भाजपा ने अपनी पूरी सरकार को ही नहीं बदला है, बल्कि सामाजिक समीकरणों को

भी काफी हद तक बदल दिया है। राज्य के 24 नए मंत्रियों में लगभग तीन-चौथाई मंत्री पाटीदार, ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय से बनाए गए हैं। इससे जाहिर है कि भाजपा भावी चुनावी समीकरणों में इन वर्गो को अपनी रणनीति के केंद्र में रखकर चलेगी। सूत्रों के अनुसार भाजपा का यह

सामाजिक समीकरण केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी इस पर काम किया जाएगा। मध्यप्रदेश में पार्टी ने दलित और आदिवासी समुदाय के बीच जाने की योजना पर काम शुरू भी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस समय दो मोर्चो पर काम कर रही है। इनमें एक सत्ता विरोधी माहौल को खत्म करना और दूसरा सामाजिक समीकरणों को साधना है। ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदाय ऐसे वर्ग हैं, जिन पर दूसरे दलों की भी निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में भाजपा इन पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। खासकर सत्ता में भी हिस्सेदारी को बढ़ा रही है, ताकि नीचे तक एक बड़ा संदेश जाए। गौरतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद अपनी सरकार के केंद्र में गरीब कल्याण योजनाओं को रखा।

चुनाव के समय ही बीजेपी को क्यों सुध आती है आदिवासियों की?- कुछ महिनों बाद प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों में ज्यादातर सीटें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की हैं। स्वाभाविक है कि केन्द्र बिंदु में आदिवासी होंगे। हो भी रहे हैं। प्रदेश की सत्तासीन सरकार एक-एक कर आदिवासियों की हितों की बातें कर रही है। आदिवासियों की हितों की योजनाएं लागू करने की बातें कर रही है। लेकिन खुद को गरीबों का हितैषी बताने वाली शिवराज सरकार को चुनावी समय में ही आदिवासियों की सुध लेना कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। हमेशा उपेक्षा के शिकार होने वाले इन आदिवासियों को समाज में बराबरी का

दर्जा दिलवाने में नाकामयाब सरकार के कार्यकाल में ही आदिवासियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि सरकार आदिवासियों को लेकर काफी सजग हो गई है। हर कार्यक्रमों में प्रमुखता से आदिवासियों की उपस्थिति, उन्हीं के बीच जाकर कार्यक्रमों का आयोजन और आदिवासी जननायकों पर केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन सीधे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सरकार इन आदिवासियों का उपयोग केवल वोटबैंक के लिए करना चाहती है। यह पहला अवसर नहीं है इससे पहले भी कई ऐसे मौके आये हैं जब इसी सरकार ने आदिवासियों का उपयोग केवल वोटबैंक की राजनीति के लिये किया है। पिछले दिनों ही खरगौन जिले में लूट के मामले में गिरफ्तार आदिवासी युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मौत का कारण पुलिस प्रताड़ना बताया है। लेकिन सरकार ने इसकी जांच करने के बजाय खानापूर्ति के रूप में तीन पुलिसकर्मियों सहित जेल के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया।

कांग्रेस की होड़ कर रही बीजेपी- पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में आदिवासियों

की सुध ली जा रही है। मजबूरन उसी राह पर शिवराज सरकार चल रही है। एक-एक कर ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे शिवराज सरकार खुद सकते में दिख रही है। इसी बीच सरकार भी कांग्रेस से होड़ करने के मूड में आ गई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आदिवासियों को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके पीछे प्रदेश सरकार भी चल पड़ती है। मध्यप्रदेश में ओबीसी पर सियासत के साथ ही अब राजनीतिक दलों ने आदिवासी वर्ग का मुद्दा पकड़ लिया है। इसे आने वाले उपचुनाव और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासी अधिकार यात्रा कर आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। इसे देख भाजपा खेमे में भी हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने इस यात्रा को धोखा करार दिया। मध्यप्रदेश में ओबीसी पर सियासत का दौर चला। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी आरक्षण ओबीसी के लिए लागू कर दिया था। इसके बाद कोर्ट में स्टे लग गया। इसके बाद केंद्र सरकार से लेकर भाजपा सरकार ने भी ओबीसी पर आरक्षण 27 फीसदी कर दिया गया। अब

मध्यप्रदेश में भाजपा के लिए चुनौती क्यों बनते जा रहे हैं आदिवासी?

आदिवासी वोटर विधानसभा की 90 सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस की स्थिति आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर हुई है। इसकी बड़ी वजह आदिवासी वोटों का विभाजन रहा है। मध्यप्रदेश में भील-भिलाला आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आदिवासियों का यह समूह निमाड़-मालवा में है। इस क्षेत्र में आदिवासियों के लिए आरक्षित तीन लोकसभा सीट रतलाम-झाबुआ, धार और खरगोन हैं। इसी अंचल की एक लोकसभा सीट खंडवा में उपचुनाव भी होना है। इस सीट पर आदिवासी वोट बेहद निर्णायक हैं। हालांकि यह सीट ओबीसी वोटों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। पिछले दो दशक में मालवा-निमाड़ के आदिवासी अंचल में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने रतलाम-झाबुआ की आदिवासी सीट को जीता था। कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया इस क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाए थे। उनके बेटे विक्रांत भूरिया विधानसभा का चुनाव हार गए थे। राज्य में आदिवासियों के लिए विधानसभा में कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। 2008 में लोकसभा एवं विधानसभा सीटों के परिसीमन से पहले विधानसभा की कुल 41 सीटें ही आदिवासियों के लिए आरक्षित थीं। राज्य में 22 प्रतिशत आदिवासी हैं। आदिवासियों की जनसंख्या में दशकीय बढ़ोतरी 25 फीसदी से अधिक की देखी गई है। राज्य में कुल आदिवासी विकासखंडों की संख्या 89 है। महाकौशल के आदिवासी इलाकों में गोंड आदिवासी हैं। आदिवासियों की आबादी के लिहाज से गोंड नंबर दो पर आते हैं। पचपन लाख से अधिक गोंड आदिवासी हैं। प्रदेश की राजनीति में यह सर्वविदित तथ्य है कि गोंडवाना के नाम के राजनीतिक दलों को कांग्रेस के नेताओं ने ही आगे बढ़ाया। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उपयोग कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए किया था। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव नए परिसीमन के अनुसार हुए इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 में से 29 सीटें जीतने में सफल रही थी जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाकर रखा। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आदिवासियों के लिए आरक्षित 30 सीटें जीतने में सफल रही थी।

कांग्रेस के प्रभाव में मालवा-निमाड़ का आदिवासी- भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल से ज्यादा चिंता मालवा-निमाड़ की होती है। मालवा निमाड़ के इलाके में आदिवासी समुदाय को हिन्दुत्व की धारा से जोड़ने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठन कई दशकों से कर रहे हैं।

इस पर`डिट के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 09 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित किया था जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस ने मजबूर किया सरकार को- यह भी सच है कि शिवराज सरकार का आदिवासियों के प्रति बड़ते रूझान के पीछे प्रदेश कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। कमलनाथ के नेतृत्व

आदिवासियों की 95 सीटों पर निर्णायक भूमिका

मध्यप्रदेश में वैसे तो आदिवासियों की आबादी 22 फीसदी है और ये विधानसभा की 95 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। लेकिन अभी मध्यप्रदेश में चार सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें खंडवा लोकसभा के अलावा जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव विधानसभा के लिए उपचुनाव है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में 08 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 04 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस क्षेत्र में 06 लाख से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं।

में प्रदेश में आदिवासियों को लेकर जो मुद्दे या मसले उठाये जा रहे हैं उससे मध्यप्रदेश सरकार मजबूरन आदिवासियों के हितों के प्रति फिक्रमंद दिख रही है। साथ ही इस समय आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। पिछले लगभग डेढ़ वर्षो से भाजपा सरकार जबसे शासन में आई है उसका ध्यान असल मुद्दों से कहीं पीछे हट गया है। यही वजह है कि जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस उन विषयों को मुद्दों बनाकर जनता के सामने पेश करती है तब प्रदेश सरकार की नींद खुलती है और वो उस तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। पिछले दिनों ऐसे कई मामले देखने को मिले जहां सरकार से पहले विपक्षी नेताओं का ध्यान गया। प्रदेश में कई जगहों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। इस बार भाजपा ने उपचुनाव में मुद्दा बनाया है पिछड़े वर्गो को साधने का। लेकिन ध्यान दिया जाये तो इसी भाजपा सरकार के कार्यकाल में पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वो चाहे आदिवासी लोगों के साथ हुई बदसलूकी का हो या फिर उनके साथ हुई मारपीट का। इन सभी मुद्दों को सत्तारूढ़ पार्टी ने तो दरकिनार ही कर दिये थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता कमलनाथ के नेतृत्व में इन मुद्दों को पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के सामने रखा। मजबूरन प्रदेश सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए इन पर कार्यवाही करना पड़ी। देखा जाये तो पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है। उसने एक नहीं कई ऐसे मुद्दे जिन पर प्रदेश सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी। उन मुद्दों को जनता के सामने लाने का कार्य किया है। जिसका फायदा पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने की पूरी उम्मीद है।

राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बहाने आदिवासियों को साधने के प्रयास-
जबलपुर में जनजातीय समाज के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस में शामिल होने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। यूं तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान जबलपुर में हुआ, लिहाज़ा ये जगह सबसे मुफीद थी लेकिन इसके सियासी निहितार्थ भी हैं। महाकौशल इलाके के आस-पास के

लगभग दस जिले आदिवासी बहुल जिले हैं। एमपी में कुल 47 सीटें जनजातियों के आरक्षित हैं जिनमें से पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 32 सीटें गईं थीं। लोकसभा के चुनाव में भले ही भाजपा ने एक तरह से एमपी में क्लीन स्वीप किया लेकिन कई जनजातीय बहुल विधानसभाओं में उसे उम्मीद से कम वोट मिले, जिसने भाजपा की फ़िक्र को और बढ़ाया है। एमपी में 2011 की जनगणना के मुताबिक एक करोड़ 53 लाख से अधिक आबादी जनजाति समाज की है। यानी सूबे लगभग हर पांचवा-छठवां व्यक्ति इसी समुदाय से आता है। लगभग 89 विकासखंड जनजाति समुदाय के बाहुल्य वाले हैं। भाजपा के लिए इस जाति को साधना बहुत मुश्किल भरा रहा है। कुल मिलाकर भाजपा का पूरा फोकस इस वर्ग को अगले चुनाव में अपने पक्ष में करने का है। देश के उन राज्यों में जहां चुनाव हैं, वहां भी इस वर्ग के लोगों के भी साधने का प्रयास है।

आखिर घटना के केन्द्र में क्यों हैं आदिवासी- पूरे मध्यप्रदेश में मालवा-निमाड़ का इलाका ही अकेला ऐसा इलाका है, जहां आदिवासी घटना के केन्द्र में है। नेमावर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की हत्या से शुरू हुई राजनीति खरगोन तक पहुंच गई। नेमावर देवास जिले में आता है। इस जिले की एक विधानसभा सीट खंडवा लोकसभा में आती है। कांग्रेस आदिवासियों पर होने वाली घटनाओं को लगातार तूल दे रहा है। नीमच में एक आदिवासी युवक को कार से बांधकर घसीटने की घटना ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। खरगोन में पुलिस पिटाई से एक आदिवासी युवक की मौत से आक्रोश बढ़ गया है। कांग्रेस ने अधिकार यात्रा निकालकर आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अधिकार यात्रा का जवाब ट्विटर पर धोखा यात्रा का कैंपेन चलाकर दिया। यह कैंपेन इस बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस की अधिकार यात्रा भाजपा के लिए चिंता का कारण बनी।

उपचुनावों को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग

मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर नियंत्रण होने के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना बाकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खंडवा-बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र, निवाड़ी, सतना और अलीरापुर जिला कलेक्टरों को लेटर लिखकर कहा है, 3 साल से एक ही जगह जमे अधिकारियों को हटाया जाए। इस दौरान चुनाव आयोग के तैयारी शुरू होते ही बीजेपी और कांग्रेस भी एक्शन में नजर आ रही है।

कांग्रेस हाईकमान को छत्तीसगढ़ संभालना बड़ी चुनौती

अत्याचार, अराजकता में डूबा छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में विगत ढाई साल से जो लूट हुई, अत्याचार हुआ वैसा इस प्रदेश ने कभी नहीं देखा था। चाहे अवैध शराब टैक्स हो या अवैध कोयला टैक्स बस हर जगह लूट ही लूट मची हुई थी। साथ में पूरा मीडिया मैनेज करने के लिए सलाहकार दलाली में लगे हैं। इस लूट अत्याचार के खिलाफ कोई लिखता या आवाज उठाता उसका दमन इस सरकार में किया जाता। चाहे पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी नौकर सबको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर केस दर्ज कर दिया जाता।

छत्तीसगढ़ में विगत ढाई साल से जो लूट हुई, अत्याचार हुआ वैसा इस प्रदेश ने कभी नहीं देखा था। चाहे अवैध शराब टैक्स हो या अवैध कोयला टैक्स बस हर जगह लूट ही लूट मची हुई थी। साथ में पूरा मीडिया मैनेज करने के लिए सलाहकार दलाली में लगे हैं। इस लूट अत्याचार के खिलाफ कोई लिखता या आवाज उठाता उसका दमन इस सरकार में किया जाता। चाहे पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता या सरकारी नौकर सबको सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर केस दर्ज कर दिया जाता। इन ढाई साल में सत्ता का जो नशा

भूपेश बघेल पर चढ़ा उसने आम छत्तीसगढ़िया को परेशान कर छोड़ा। चाहे किसान हो, छोटा व्यापारी, सरकारी नौकर सब इस सरकार के रवैए से परेशान रहे। असली में सरकार तो सुपर सी.एम महिला अधिकारी, दागी आई.ए.एस. और सलाहकारों मिल कर चला रहे हैं। भूपेश बघेल का साहस इतना बढ़ गया की अभी हाईकमान के मना करने के बावजूद 56 विधायकों को दिल्ली में डेरा डलवा दिया। वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं इसके लिए वो पार्टी भी तोड़ सकते है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की सरकार में एक बार फिर अंदरूनी उथल पुथल देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमने-सामने हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 90 में से 70 सीटें है। सरकार चलाने के लिए पार्टी के पास प्रचंड बहुमत है। पंजाब, एमपी और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ भी अंदरूनी

गुटबाजी से जुझ रही है। सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद यह गुटबाजी चरम पर आ गई है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव में ठनी है। खुलकर दोनों एक-दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते लेकिन इनके समर्थकों में टकराव बनी रहती है। इस पूरे टकराव के पीछे की वजह ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला है। देखा जाए तो दोनों ही कांग्रेसी नेताओं के बीच आपसी टकराव होने की जानकारी कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। बावजूद उसके कांग्रेस शीर्षस्थ खेमा राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे है। जबकि चुनाव जीतने के बाद आलाकमान ने इस बात पर सहमति जताई थी कि ढाई साल का कार्यकाल भूपेश बघेल और ढाई साल का कार्यकाल टीएस

सिंहदेव का होगा। लेकिन कांग्रेसी नेता अब तक इस पर कोई निर्णय़ नहीं ले पाए है। अगर भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल का आंकलन करें तो इस सरकार में पहली बार अराजकता, लूटपाट, चोरी, छेड़छाड़ सहित भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यह सरकार इस सभी पर रोक लगाने में असफल साबित हुई है। लेकिन भूपेश बघेल अपने किये पर पर्दा डालते हुए कांग्रेस शीर्षस्थ बैठे नेताओं को राज्य के बेहतरी संचालन की सूचना देते है। इतना ही नहीं भूपेश बघेल के किये की जानकारी आलाकमान तक न पहुंचे इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र पत्रकारों के लिखने की आजादी पर बैन लगा दिया है। कोई भी पत्रकार अगर उनके सरकार के भ्रष्टाचार और कामचोरी के खिलाफ लिखता है तो उसे तुरंत जेल में भेज दिया जाता है या फिर उसे धमकियां दी जाती है। कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने अपने चहेते दो-तीन राष्ट्रीय चैनलों को प्राथमिकता देते हुए सरकार की ब्रांडिंग करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। बीते एक महीने में दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ गया है। इस सुलझाने के लिए दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पंचायत करनी पड़ी है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव को उन्होंने आमने-सामने बैठाकर बात की है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। लेकिन मामला अब भी शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान और पंजाब में घमासान मचा ही है कि छतीसगढ़ का विवाद भी खुलकर सभी के सामने आ गया है। चुनावों से पहले कांग्रेस ने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मेहनत की बदौलत अपनी पकड़ मजबूत की और 15 साल बाद सत्ता हासिल कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा फैसला यह है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस पर संशय बना हुआ है, फिलहाल भूपेश बघेल ने बाजी मार ली, लेकिन परदे के पीछे दोनों के बीच क्या समझौता हुआ था उसकी झलक अब दिखाई दे रही है। लगता है कि उस समय जैसे-तैसे कांग्रेस अपनी कमजोरी छुपाने में कामयाब रही, लेकिन अब वहीं बात जगजाहिर हो रही है। चर्चा है कि कांग्रेस ने ढाई-ढाई साल वाला फार्मूला सुझाया था। ऐसे में भूपेश की बारी

भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल का आंकलन करें तो इस सरकार में पहली बार अराजकता, लूटपाट, चोरी, छेड़छाड़ सहित भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यह सरकार इस सभी पर रोक लगाने में असफल साबित हुई है। लेकिन भूपेश बघेल अपने किये पर पर्दा डालते हुए कांग्रेस शीर्षस्थ बैठे नेताओं को राज्य के बेहतरी संचालन की सूचना देते है। इतना ही नहीं भूपेश बघेल के किये की जानकारी आलाकमान तक न पहुंचे इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्र पत्रकारों के लिखने की आजादी पर बैन लगा दिया है।

पूरी होने पर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने का इंतजार करने लगे, लेकिन कांग्रेस ने तो अपने ही फार्मूले को भुला दिया। नेतृत्व संकट का सामना कर रही कांग्रेस विवाद उलझने के बाद ही क्यों सक्रिय होती है। जब उन्होंने फार्मूला सुझाया था तो उन्हें खुद विवाद को सुर्खियां बटोरने से पहले ही सुलझाना चाहिए था, लेकिन सुलझाता कौन? क्योंकि कांग्रेस खुद बीमार चल रही पाना काफी मुश्किल है। राहुल और प्रियंका की जोड़ी कुछ मोर्चों पर पहले सफल हो चुकी है, लेकिन जहां उन्हें सफलता मिली थी वहां वक्त और परिस्थिति दोनों भिन्न थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से लगातार घमासान चल रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ढाई-ढाई वाला फार्मूला मानने को कहा है। इस प्रकार के समाचार भी मीडिया की निर्णय हाईकमान के पास ही सुरक्षित है। आलाकमान जो निर्णय लेगा वह हमें स्वीकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में कुछ विधायक और मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल रखा है। इस बारे में सिंहदेव ने कहा था कि जो लोग अपनी मंशा से दिल्ली गए थे उनकी बात वो जानें, लेकिन विधायकों को हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया है। अगर वे किसी अन्य वजह से जाना चाहते हैं तो स्वतंत्र

है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसीलिए तो नेतृत्व को लेकर 23 नेताओं ने सवाल खड़ा किया था। जिसे जी-23 का नाम दिया गया और फिर उन्हें निशाना भी बनाया गया, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए सवालों का समाधान नहीं निकला। फिलहाल राहुल और प्रियंका मिलकर विवादों को सुलझाने का प्रयास कर हैं, लेकिन विवाद कब खत्म होगा, यह कह सुर्खियां बन चुके हैं। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा के बीच रायपुर छतीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने नेतृत्व परिवर्तन के मामले में मीडिया से चर्चा के दौरान कहा है कि यह निर्णय पार्टी आलाकमान के पास है। सिंहदेव ने यह भी स्वीकार किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनकी लंबी बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दे शामिल थे। हालांकि अंतिम है। गौरतलब है कि छतीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के ढाई साल पूरे करने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए ढाई-ढाई साल वाले फार्मूले की चर्चा जोरों पर चल रही है। राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल सहित अन्य नेताओं की बैठक के बाद चर्चाओं का बाजार लगातार गरमा रहा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर विवाद थमा नहीं है।

प्रकृति, आदिवासी बिरहोर ओर झारखंड

विजया पाठक

15 नवंबर को झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप मे स्वीकृत किया गया था यह राज्य पहाड़ी व जंगली भूमि के राज्य के रूप में जाना जाता है। खनिज संपदा से भरा पूरा होने के कारण इसे 'रत्नगर्भा' की संज्ञा भी दी जाती है। झारखंड राज्य की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 27.67 है। सन् 1912 में बंगाल विभाजन के समय छोटा नागपुर को बिहार में विलय किया गया था इस इलाके में अपार खनिज संपदा का आभास होने पर गैर आदिवासी क्षेत्र की जनता ने यहां आकर यहां के संसाधनों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। 1915 में छोटा नागपुर उन्नत समाज के नाम से संगठन का निर्माण कर आदिवासियों ने अपने क्षेत्र को पृथक करने की मांग प्रारंभ की। 1937 के प्रथम चुनावों के पश्चात 1945 में रीजनल झारखंड राज्य की मांग की गई थी। आदिवासी संस्कृति की विषय 72 वर्ष पश्चात 15 नवंबर 2000 को पूर्ण हुई थी। अगर झारखंड को आदिवासी प्रदेश कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। झारखंड के जनजातीय लोगो का निवास इस राज्य के मुख्यतः छोटा नागपुर के पठारी इलाके में तथा राजमहल के पहाड़ी इलाके रांची, हजारी बाग, पलामू गिरीडीह, धनवाद सिंह भूमि, संथाल, परगना आदि जिलों में निवास करती है। झारखंड में 9 चिन्हित आदिमजातियों को मिश्रित कर कुल 32 जनजातियां है। सौरिया, खडिया, कोरवा, बिरजिया, बिरहोर, असुर एवं सावर जातियों की जनसंख्या अन्य जनजातियों की जनसंख्या

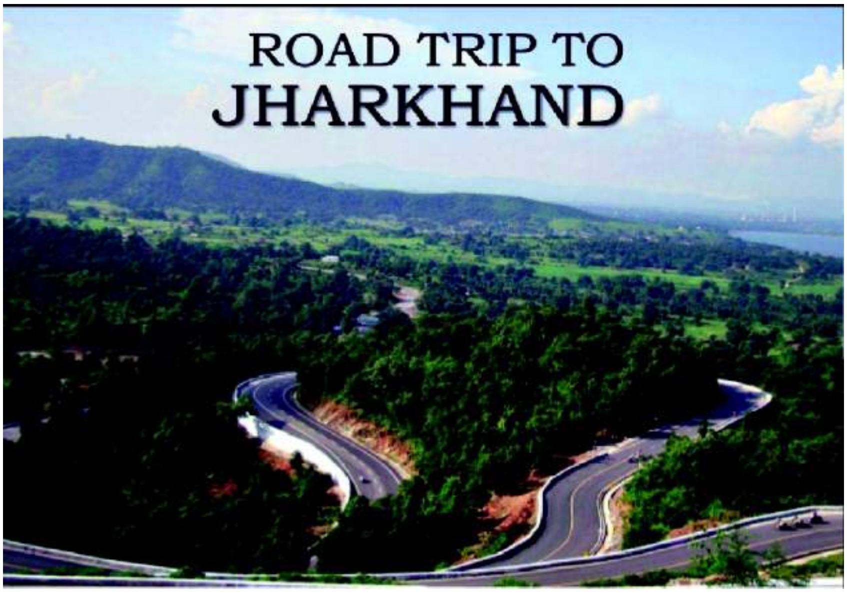

का मात्र 3.41 प्रतिशत है।

झारखंड में एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति की जनजाति है जिसे बिरहोर कहा जाता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है बिर जंगल होर मनुष्य अर्थात जंगल या वनों में रहने वाला मनुष्य। यह जनजाति छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर पूर्व से हजारीबडा कोडरमा, जलागू बांकारो जिले में पाई जाती है। चूंकि यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते है और इनका जो निवास स्थान होता है उसे हाडा कहा जाता है। सामान्यता इस जनजाति को पृथक निवास की प्रवृत्ति होती है। इस जनजाति को दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम उथालों एवं द्वितीय जाधी उथालों, मुख्यतः ये लोग लगभग निष्क्रिय जीवन जीते है। शिकार एवं खाद्य संग्रहण के आधार पर ये जनजाति अपना जीवन यापन करती है। बिरहोर को सबसे पिछड़ी जनजाति माना जाता है जो एकदम सत्य है। बिरहोर जनजाति की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। परिणाम स्वरूप इस जनजातीय समुदाय में लगभग 5000 के आसपास आबादी है जो 700 परिवारों में विभाजित है। बिरहोर जनजाति संयुक्त परिवार की परंपरा में विश्वास करते है। दस बारह वर्ष की उम्र एवं उससे बड़ी संताने शयन ग्रह में रहती है। जिसे बिरहोर जनजाति में गत्योरा कहा जाता है। युवा लड़का लड़की का गत्योरा प्रथक कर दिया जाता है। एक पत्नी रखने की परंपरा विद्यमान है। फिर भी बहुपत्नि प्रथा प्रचलित है। बाल विवाह प्रथा का प्रचनल नहीं है। आपसी विवादों का निपटारा पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। पंचायतों में परिवर्तन होता रहता है। बिरहोर जनजाति में देवालय बड़ा व अहम होता है। बोरा एवं बोगा इनके प्रमुख देवता है। इस जनजाति में परिवार पितृसत्तात्मक होते है। इनके परिवार जीविका एवं शिकार के चक्कर में एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते रहते हैं। इनके शिकार में चूहा, गिलहरी, हिरण, जंगली बंकरा कई प्रकार की चिकियां आदि शामिल होती है। ये लोग शिकार में लाठी, फंदा, रस्सी जाल, कुल्हाणी आदि प्रमुख है। ये जनजाति शिकार के आलावा शहद मोम का संकल रस्सी बनाने के लिए चोच का संग्रह करते है। इस जाति में पशुपालन भी किया जाता है। बकरी, कुत्ता, सुअर, मुर्गी आदि को पाला जाता है। यह जनजाति प्रकृति को ताल में ताल मिलाकर अपना जीवन यापन करती है। और इस जनजाति की गणना उंगली पर की जा सकती है। इस परिपेक्ष्य में सरकारी ने कई योजनाएं क्रियान्वित की मगर इन योजनाओं का लाभ इस जनजाति को न के बराबर मिला है। कृषि के पिछड़ेपन वन्य संपदाओं के निविर्चन उपयोग पर रोक, अविकसित संसाधन तथा अन्य विषम कारणों के चलते ये जनजाति आर्थिक रूप से टूट रहे हैं। और आज भी ये शिकार कर अपना पेट पाल रहे हैं। निर्धनता एवं अभाव ग्रस्त जीवन के चलते ये जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। और अगर इन जनजातियों पर दृष्टिपात कर उचित कदम नहीं उठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब मात्र कल्पनाओं में कहानी, अखबार, फिल्मों के माध्यम से इन जनजातियों के बारे में जान सकेंगें।

अतः सरकार की कल्याणकारी योजनाऐं मात्र रिपोर्ट न होकर जनजातीय इलाके तक पहुंचे व सदियों से प्रकृति का साथ निभाने वाली जनजातियों को वसुंधरा पर बसाया जाये ताकि गर्व से झारखंड कह सके प्रकृति, बिरहोर और झारखंड।

सख्त कानूनों से भी नहीं घट रहे बलात्कार के मामले

नवीन शर्मा

दिल्ली में एक नौ साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना ने देश को फिर विचलित कर दिया है। श्मशान में पहले बलात्कार, फिर हत्या और वहीं अंत्येष्टि कर देने की यह घटना अत्यंत भयानक है। फिर वही सवाल उठने लगा है कि यह सब आखिर कब तक? इसी तरह मध्यप्रदेश के विदिशा में एक बारह साल की माासूम का बलात्कार के बाद हत्या कर शव को पेड़ पर टांग देने की घटना सामने आई है। ऐसे घटनाएं क्रुरतम स्वरूप में ही सामने आ रही हैं। अब यह समाज बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाली इन घटनाओं पर अधिक चर्चा इसलिए भी नहीं करता, क्योंकि ये खबरें सामान्य खबरों की तरह आम हो गई हैं। एक घटना से सुर्खियां मिलने पर विरोध की मुहिम चला दी जाती है और कुछ ही दिनों में सब भूल जाते हैं। अपराध की हर घटना अपने पीछे न्याय के सवाल छोड़ जाती है, फिर भी हम उनका उतर क्यों नहीं खोज पाते?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में हर दिन बलात्कार के अट्ठासी यानी कुल 3233 ममाले दर्ज हुए। पिछले दस वर्षो में बलात्कार की घटनाएं चौवालीस फीसदी बढ़ गई हैं।

केरल में सत्रह वर्षीय लड़की का अड़तीस लोगों द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला हो या बदायूं, हाथरस में घटित घटना, सब उन्हीं प्रश्नों को उभारती हैं, जो 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के बाद उठे थे। लगभग नौ साल पहले हुई उस घटना पर जनाक्रोश के बाद गठित जस्टिस जेएस वर्मा समिति की अनुशंसा पर बलात्कार निरोधक कानून बना था। साथ ही निर्भया कोष की स्थापना की गई। वर्ष 2019 में पॉक्सो कानून में संशोधन कर बारह वर्ष से

कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण पर सजा-ए-मौत का प्रावधान किया गया। ये वे वैधानिक प्रयास थे, जिनका लक्ष्य कठोर दंड के भय से अपराध को रोकना और अपराधियों को दंडित करना था, पर सवाल है कि अपराध को रोकने में सार्थक भूमिका निभाई है ? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि निर्भया मामले के बाद महिला अपराध के बलात्कार की घटनाएं चौवालीस फीसदी बढ़ गई हैं। 2019 में आधे से अधिक मामले पांच राज्यों- राजस्थान, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और केरल के थे। ये वे मामले हैं जो पुलिस थानों में दर्ज कराए गए। सामाजिक प्रतिष्ठा या अन्य कारणों से डर से जो अपराध रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराए गए, वे अलग हैं। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य था, भी अपराध के इस घृणित स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आया। लगा था कि इस दौर में मानवता पुनर्जीवित हो उठेगी, पर पूर्णबंदी के समय भोपाल में दृष्टिहीन महिला के साथ बलात्कार की घटना ने इस भ्रम को तोड़ दिया। उन्हीं दिनों झारखण्ड के दुमका में बंदी खुलने के बाद गांव लौट रही एक सोलह वर्षीय छात्रा से दस युवकों ने सामूहिक

आंकड़े लगातार बढ़े हैं। केन्द्र सरकार ने 2015 से 2019 के बीच देश में बलात्कार के 1.17 लाख मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में हर दिन बलात्कार के अट्ठासी यानी कुल 3233 ममाले दर्ज हुए। पिछले दस वर्षों में जिसने मंदसौर में स्कूली छात्रा के साथ हुए बलात्कार के बाद फांसी की सजा का प्रावधान किया था, मगर आज उसी मध्यप्रदेश बारह वर्षीय मासूम से बलात्कार और उसकी हत्या के बाद उसका शव पेड़ पर टांग देने की घटना सामने आई है।

पिछले साल कोरोना महामारी के दौर में बलात्कार किया। उत्तरप्रदेश के शामली जिले में राशन देने आए दुकानदार ने महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार किया। नोएडा में आठ साल की मासूम बच्ची गंभीर हालात में सलारपुर गांव के पास झुग्गियों में मिली। एक लंबी फेहरिस है, जो बलात्‍ार की अनवरत घटनाओं को बयान करती और

बताती है कि कानून बना देने से अपराध में कमी नहीं आती। आम धारणा है कि सख्त कानून अपराध को रोकने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे। इसी के चलते बलात्कार निरोधक कानून बना और पॉक्सो कानून में संशोधन किया गया, पर ऐसे अपराधों में कोई कमी नहीं आई। सवाल है कि कानून में सख्त सजा के प्रावधान, शीघ्र न्याय के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना, निर्भया कोष में प्रतिवर्ष धन आवंटन के बाद भी हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? आरोपी कानून की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, जिससे नागरिक समाज का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता नजर आ रहा है। न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संकट से जूझ रही है, न्यायपालिकाओं पर मुकदमों

निर्भया कोष में प्रतिवर्ष धन आवंटन के बाद भी हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? आरोपी कानून की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, जिससे नागरिक समाज का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता नजर आ रहा है। न्याय व्यवस्था न्यायाधीशों के रिक्त पदों के संकट से जूझ रही है, न्यायपालिकाओं पर मुकदमों का बोझ निरंतर बढ़ रहा है, न्याय की गति धीमी बनी हुई है

का बोझ निरंतर बढ़ रहा है, न्याय की गति धीमी बनी हुई है, ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का मनोबल बढ़ता है। बलात्कार निरोधक कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई त्वरित अदालतों में करने का प्रावधान है। इसके लिए एक हजार तेईस विशेष त्वरित अदालतों की जरूरत है। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने इस पर 767.25 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है। जब तक ये विशेष अदालतें आकार नहीं ले लेतीं और परिणाम कानून में निहित प्रावधानों के तहत आने शुरू नहीं हो जाते, तब तक इस कानून की सार्थकता सिद्ध नहीं हो सकेगी। विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन पचास होना

चाहिए। यानी पदों की संख्या बढ़ाकर तीन गुना करना होगी। आबादी के ताजा आंकड़ों के हिसाब से देश में पैंसठ हजार अधीनस्थ न्यायालयों की आवश्यकता है, लेकिन इस वक्त 15 हजार न्यायालय भी नहीं है। त्वरित अदालतों के गठन के साथ न्यायपालिकाओं में रिक्त पदों को भरना भी आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने निर्भया कोष के तहत आवंटित कुल बजट के बीस प्रतिशत से भी कम हिस्से का उपयोग किया है। उल्लेखनीय है कि 2015 से 2018 के बीच केन्द्र सरकार द्वारा निर्भया कोष में 854.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें से मात्र 165.48 करोड़ रुपए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने खर्च किए। निर्भया कोष में मुख्य रूप से इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम, वन स्टॉप स्कीम, महिला पुलिस वालंटियर जैसी योजनाओं पर खर्च का प्रावधान है। मगर कई राज्य तो ऐसे हैं, जिन्होंने इस कोष का एक भी रूपया इन योजनाओं पर खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मणिपुर और केन्द्र शासित राज्य लक्षदीप हैं। ऐसे में इस कोष का औचित्य क्या रह गया? अपराधमुक्त समाज के लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। इस राह में आ रहे तमाम गतिरोधों को दूर करने के प्रयास होना चाहिए।

■ बलात्कार के मामलों में सजा की दर अब भी मात्र 27.2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2018 में बलात्कार के 1,56,327 मामलों में मुकदमे की सुनवाई हुई।

■ इनमें से 17,313 मामलों में सुनवाई पूरी हुई और सिर्फ 4,708 दोषियों को सजा हुई। 11,133 मामलों में आरोपी बरी किए गए, जबकि 1,472 मामलों में आरोपियों को अरोपमुक्त किया गया।

■ किसी मामले में आरोपमुक्त तब किया जाता है जब आरोप तय न हों। वहीं आरोपियों को बरी तब किया जाता है जब मुकदमें की सुनवाई पूरी हो जाती है।

■ खास बात यह है कि 2018 में बलात्कार के 1,38,642 मामले लंबित थे। बलात्कार के मामलों में सजा की दर 2018 में पिछले साल के मुकाबले घटी। 2017 में सजा की दर 32.2 प्रतिशत थी।

दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर उठते सवाल

अर्चना शर्मा

दल बदल का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना समय हमें अंग्रेजों से आजादी मिलकर हो चुका है। स्वतंत्रता के बाद से राजनीतिक दल बदलने की आदत शुरू हो गई थी, जो अब तक जारी है। इससे बचने के लिए कानून भी बनें लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। कर्नाटक में दल बदल की वजह से एचडी कुमारस्वामी को अपना पद गंवाना पड़ा था। थोड़ा पीछे चलते हैं। या यूं कह लीजिए कि आजादी के तुरंत बाद के दौर को टटोलने की कोशिश करते है। 1948 ईस्वी की बात है। कांग्रेस समाजवादी दल ने अपने सारे विधायकों को अपने पद से इस्तीफ़ा देकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने को कहा। इसके पीछे की मुख्य वजह सभी विधायकों द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला था। इस फैसले को सर्वसम्मति से मानने में आचार्य नरेंद्र देव जैसे दिग्गज नेता भी शामिल थे। पूरे राजनीतिक इतिहास में यह घटना आज भी एक मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। एक दौर वह भी था जब

साल 1967 से लेकर 1971 के बीच कुल 142 सांसदों ने दल बदल किया। इतना ही नहीं इसी दौर में कुल 1,969 विधायकों ने दल बदल कर इतिहास रच दिया। आपको जानकर ताजुब होगा कि इस दल बदल की वजह से कुल 32 चुनी हुई सरकारों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था।

दल बदल विरोधी कानून के बिना ही राजनेताओं की सत्यता, संबलता और दृढ़ता उजागर होती थी। इसके बाद शायद ही ऐसा कोई उदाहरण भारतीय राजनीति के इतिहास में देखने को मिलता है। ऐसे बनी आया राम और गया राम कहावत- अब आपको 1960 से 1972 ईसवी के दौर में ले चलते हैं। यह दल बदल करने के लिहाज से सबसे स्वर्णिम दौर माना जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि साल 1967 से लेकर 1971 के बीच कुल 142 सांसदों ने दल बदल किया। इतना ही नहीं इसी दौर में कुल 1,969 विधायकों ने दल बदल कर इतिहास रच दिया। आपको जानकर ताजुब होगा कि इस दल बदल की वजह से कुल 32 चुनी हुई सरकारों को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। आपने आया राम और गया राम वाली कहावत भी जरूर सुनी होगी। अक्टूबर 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया

जब सीमित हुई मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या

साल 1997 का दौर कौन भूल सकता है। जब कल्याण सिंह की सरकार से मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद जो हुआ वह भारतीय राजनीति के इतिहास में अनूठा वाकया था। समर्थन के लोभ में कल्याण सिंह ने 93 सदस्यीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया था। इतनी संख्या तो छोटे राज्यों में पूरे विधानसभा की भी नहीं होती है। अंततः साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संसद में 91वां संविधान संशोधन पेश किया और उसे मंजूरी मिल गई। इस कानून के तहत न सिर्फ व्यक्तिगत दल बदल बल्कि सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक घोषित किया गया और दो तिहाई की संख्या के साथ दल बदल को सिर्फ मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की संख्या को भी सीमित किया गया। कानून तो बना लेकिन असर कम हुआ लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से दल बदल होता गया वह अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। साल 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से दल बदल हुआ और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, वह कहीं न कहीं दल बदल विरोधी कानून को भी कटघरे में खड़ा करता है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच हुए दरार को भी इसी कानून से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार और शरद यादव की कटुता को भी दल बदल विरोधी कानून से उजागर किया जा सकता है। साल 2017 में मणिपुर विधान सभा का मामला हो या फिर साल 2020 में राजस्थान और मध्यप्रदेश में हुए सियासी बबंडर का हो, सभी जगह दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिता का सवाल खड़ा होता है। हालांकि 91वें संविधान संशोधन के बाद जरूर दल बदल में पहले से काफी कमी आई है लेकिन सामूहिक दल बदल के मामलों में जितनी कमी देखी जानी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई है।

लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार पार्टी बदली। वह पलवल विधानसभा क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनकर सदन पहुंचे थे। यह वाकया भी इतिहास के पन्नों में जुड़कर रह गया। लालच देकर सरकार गिराई- ऐसी कई सारी कहानियां और किस्से भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय संविधान और कानून को तार-तार करने के लिए काफी हैं। आप बात चाहें 1967 में मध्यप्रदेश में गोविंद

17 महीने में पांच मुख्यमंत्री

कानून बन जाने के बाद भी नागालैंड (1988), मिजोरम (1988), कर्नाटक (1989), गोवा (1990), नागालैंड (1990), मेघालय (1991), मणिपुर (1992), नागालैंड (1992) और मणिपुर (2001) में काफी जबरदस्त तरीके से दल बदल किया गया। सवाल उठना लाजमी था क्योंकि कानून के प्रावधानों को लागू करने के बजाय वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1998-99 में गोवा काफ़ी सुर्खियों में रहा। 17 महीने के अंदर गोवा में पांच मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ी। फिर बाद में चार महीने (फरवरी-जून 1999) राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

नारायण सिंह सरकार को गिराने की करें या फिर 1980 में हरियाणा में पूरी भजनलाल कैबिनेट का कांग्रेस में शामिल होने की करें। प्रत्येक पहलुओं पर अगर ध्यान दिया जाएं तो कहीं न कहीं दल बदल का इतिहास काफी कलंकित रहा है। सबसे शर्मनाक हरकत तो तब हुई जब साल 1983 में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा और एनटी रामाराव मुख्यमंत्री के रूप में चुनकर सदन पहुंचे। अगले ही साल साल 1984 में रामाराव के विदेश जाने पर कांग्रेस ने उनकी पार्टी के एक मंत्री को मुख्यमंत्री पद का ऑफर देकर तोड़ दिया और हद तो तब हो गई जब वहां के तत्कालीन रायपाल ने आनन-फानन में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलवा दी। इससे न सिर्फ दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठा बल्कि रायपाल जैसी मर्यादित और संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा। हालांकि फिर कुछ दिनों के बाद रामाराव ने राष्ट्रपति के सामने सारे विधायकों की परेड करवाई और फिर से जाकर उनकी सरकार बन पाई। ऐसी कई घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है।

दल-बदल प्रथा पर कानून अंकुश का प्रयत्न- साल 1985 को भी याद करना लाजमी होगा, जब राजीव गांधी की सरकार ने 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल-बदल विरोधी कानून को पारित कर एक नया इतिहास रचा। साथ ही संविधान में 10वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। इस कानून के तहत देश में आग की तरह से फैल चुकी दल-बदल प्रथा को रोकना था। कुल मिलाकर कई सारे प्रावधानों को मंजूरी दी गई। एक प्रावधान ऐसा था जिसपर बहुत सवाल भी खड़े किए गए। दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत एक तिहाई सदस्य साथ में दल बदल कर सकते थे। इसके बाद भी दल बदल प्रथा पर कुछ खास अंकुश नहीं लग पाया। इस कानून में लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्षों के अधिकारों के दायरे को भी बढ़ा दिया गया। दल बदल विरोधी कानून के रहते वी. पी. सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। उस दौर में किस प्रकार जोड़तोड़ हुआ होगा इसपर यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फर्क इतना रह गया था कि पहले लोग अकेले भी दल बदल कर लिया करते थे लेकिन इस कानून के आ जाने के बाद थोक भाव में दल बदल प्रारंभ हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि इसे देश की सबसे ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई। नवंबर 1991 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 3:2 के अनुपात में दल विरोधी कानून के पक्ष में आया। 03 जजों ने इस कानून को सही ठहराया जबकि 2 जजों ने इसे संवैधानिक करार दिया।

मंथन से निकला बक्सवाहा जंगल बचाने का अमृत

आजीविका के लिए आर-पार की लड़ाई करने को मजबूर बक्सवाहावासी

विजया पाठक

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से सटे बक्सवाहा में हीरे की खुदाई के लिए करोड़ों पेड़ काटे जाने को लेकर स्थानीय लोगों का संघर्ष अब भी जारी है। आज भी ग्रामीण अपना कामकाज छोड़ दिन भर इधर से उधर जंगल और जमीन बचाने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बक्सवाहा जंगल को बचाने की मुहिम तेज होती जा रही है। धीरे-धीरे कर देश भर के पर्यावरण प्रेमी इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में नैनागिरी में भारत के 09 राज्यों-मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों के पर्यावरणप्रेमियों ने दो दिवसीय मंथन शिविर में शामिल होकर जंगल बचाओ अभियान को बल दिया। इस शिविर में देशभर के पर्यावरणविद, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, जनांदोलन से प्रमुख कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। साथ ही नैनागिरी तीर्थ कर वन वाटिका में नीम, पीपल, वटवृक्ष आंवला, जामुन के पौधों लगाए।

कार्यम में केन बेतवा बचाओ आंदोलन से जुड़ी विजया पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता

आदिमानव काल के हैं शैलचित्र

आदिमानव काल के शैलचित्र आज भी वहां देखने को मिलते हैं। जो करीब तीस हजार साल पुराने हैं। इसकी खोज भारतीय पुरात्व विभाग की टीम ने खोज की। यह मामला प्रदेश के हाईकोर्ट के संज्ञान में भी है और उसने भी अपनी रिपोर्ट मे कहा है बक्सवाहा के जंगलों में मिलने वाले शैलचित्रों के बारे में अनुमान है कि यह 20,000 से 30,000 वर्ष पुराने हो सकते हैं। इन शैलचित्रों की जानकारी हाईकोर्ट में अ ार्कियोलॉजी विभाग ने दी है। जिनका दावा है कि यह शैलचित्र आदिमानव की 46 प्रजातियों की मानी जा रही है। यह शैलचित्र रॉक पेंटिंग लाल रंग से चट्टानों मे उखेरे गये है, जिन्हे संरक्षित करने जरूरत है और इन पर पुरातत्व विभाग रिसर्च करने की और जरूरत है। ताकी इन शैलचित्रों को संरक्षित किया जाता है तो इस क्षेत्र में इस रॉक पेंटिंग की वजह से इन जंगलो मे पयर्टन क्षेत्र विकसित कर यहां रोजगार की उम्मीद जगाई जा सकती हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां एक रॉक पेटिंग लाल रंग की है यह आग की खोज से पहले की बताई गई है। दूसरी पाषाण युग से मध्यकाल के बीच की है, ये लाल रंग और चारकोल से बनाई गई है। तीसरी रॉक पेंटिंग मानव इतिहास को दर्शाती है, जिसमें पहाड़ों और गुफाओं पर युद्ध के चित्र उकेरे गए हैं। दो दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन नैनागिरि, बक्सवाहा में 25 एवं 26 सितंबर 2021 को किया गया था। शिविर मंथन में सभी ने तर्क सहित अपनी बातों को प्रमुखता रखा, जिसमें पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, पत्रकार दीपेश स्वामी, राष्ट्रीय लक्षण मंच के राकेश विश्नोई, पर्यावरणप्रेमी संतराम अहिरवार, समाजसेवी रविन्द्र शर्मा, एडवोकेट राकेश यादव, सन्नी कुमार, गीता यादव, लीला पंवार, हरिओम पंवार, अंकुर जैन, विशाल जैन, गुड़िया ठाकुर, केशव सिंह कीर्ति पर्वतारोही, गोपी सौर ट्री मेन बक्सवाहा, निखिल जैन जीव जंतु रक्षक एवं अन्य सभी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।

राजेश यादव, सोशल एक्टिविस्ट एवं पीपल, नीम, तुलसी अभियान के संस्थापक डॉ. धर्मेंद्र कुमार, वृक्ष मित्र सुनील दुबे, एडवोकेट आराधना भार्गव, पर्यावरण प्रेमी, अनुराग बिश्नोई, रिटायर्ड आईएएस सुरेश जैन आदि ने जंगल बचाओ अभियान की आगामी रणनीति पर विचार एवं सुझाव दिए। शिविर में न्याय प्रयिा एवं मुख्य पहलू पर चर्चा, कटते जंगल उजड़ता आशियाना, बेजुबान पशु-

पक्षी, जीव-जंतु की आवाज कैसे बने? जंगल पर आश्रित परिवारों की दशा और दिशा इन विषयों पर प्रमुखता से मंथन किया गया।

शामिल प्रतिभागियों ने मिट्टी तिलक, मिट्टी से स्नान, वृक्षारोपण, हस्ताक्षर अभियान, रात्रि सभा, रात्रि मशाल जुलूस और रैली निकाली एवं माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस परियोजना पर रोक लगाने के लिए एक सुर में आवाज उठाई। सभी ने वचन भी दिया कि हम देश में जहां भी जल, जमीन, जंगल और प्रकृति का हनन होगा वहां पर हम आवाज बनकर प्रकृति के साथ खड़े रहेंगे।

कार्यशाला में डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, सुनील दुबे और सुरेश जैन ने अपने उदबोधन में कहा कि देश में प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा हम सभी ने कोरोनाकाल में सांसों के संकट से हम गुजर चुके हैं। देश में सोना, चांदी, हीरे, ज्वैलरी बेचकर भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, हमें प्राकृतिक ऑक्सीजन बैंक बनाने की जरूरत है। बक्सवाहा में जिन 07 स्थानों पर शैलचित्र हैं, उन्हें विश्व धरोहर में शामिल किया जाए और उसके संरक्षण को लेकर सरकार काम करे। मंथन में सभी ने तर्क सहित अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। गौरतलब है कि बक्सवाहा बंदर प्रोजेक्ट के तहत 382.131 हेक्टेयर वनभूमि से 2 लाख 15 हजार 875 पेड़ो की कटाई कर 3.42 करोड़ के हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। जिससे बक्सवाहा के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। परियोजना में 17 गांवों के सीधे तौर पर 4500 परिवार से 20 हज़ार की जनसंख्या प्रभावित होंगे। वनवासी और जंगल पर आश्रित समुदाय के जीवन पर सांसों व आजीविका का संकट गहराता जा रहा है। पर्यावरणप्रेमियों ने बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान के तहत उन जंगलों को बचाने के लिए और संघर्ष किया है और सभी का अथक प्रयास से जंगल अवश्य ही बचेंगे। पिछले दिनों भी मेरा बक्सवाहा जाना हुआ था। इस दौरान मैंने ग्रामीणों की पीड़ा को करीब से जाना और उनके दर्द की मुख्य वजह को समझा। लगभग 48 घंटे से अधिक समय मैंने उनके साथ बिताया। अपना राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य के साथ प्रदेश सरकार हीरे की खुदाई की परमिशन पहले ही बिड़ला समूह को दे चुकी है। लेकिन सरकार इस बात से अब भी अंजान है कि जिस जमीन को वो चंद हीरों की खुदाई के लिए बिड़ला समूह के सुपुर्द कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी इस पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर संवेदनशील रहते हैं, ऐसे में उन्हें इस प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगाकर इस स्थान को भी भीमबैठिका या अन्य पर्यटन स्थल की तरह विकसित करना चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र के हजारों लोगों की आजीविका पर भी ध्यान देना चाहिए। यही कारण है कि अब इसके प्रोजेक्ट को लेकर बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। मशाल जुलूस में शामिल हुए हजारों लोग बक्सवाहा क्षेत्र के आदिवासी गांव मानकी गांव में बड़े स्तिर पर मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव के 200 परिवारों के लोगों ने खदान आंवटन का विरोध किया। जुलूस में शामिल महिलाओं ने कहा कि हम आखरी दम तक इस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे क्योंकि यहां के जंगलों के कटने से हमारी रोजी-रोटी ही चली जाएगी।

ममता बनर्जी की निगाहें भवानीपुर उपचुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली पर

अमित राय

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेबाल को शिकस्त दी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद पर रहने का रास्ता साफ हो गया है। सांविधानिक बाध्यता के कारण उन्हें पांच नवंबर से पहले किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव जीतना अनिवार्य था। यह चुनाव केवल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए नहीं था बल्कि इसकी चुनौती इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। राजनीति के जानकार इस जीत के कई मायने निकाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ममता की जीत की यह लहर पश्चिम बंगाल की सीमा से बाहर निकलकर 2024 के लोकसभा चुनाव को छूने के लिए है। इससे देश की राष्ट्रीय राजनीति के भी प्रभावित होने की पूरी संभावना है और अब ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुद को प्रमुख दावेदार के तौर पर पेश कर सकती हैं। ममता बनर्जी के इस चुनाव अभियान के केंद्र में राष्ट्रीय राजनीति थी। विश्लेषकों की मानें तो अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में हार जातीं, तो न केवल राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की उनकी योजना और रणनीति विफल हो जाती, बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता।

भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत कोई मुद्दा नहीं थी। ममता का लक्ष्य था जीत के अंतर को बढ़ाना और भवानीपुर से पूरे देश को संदेश देना। टीएमसी को इसमें भारी कामयाबी मिली है। अब ममता का लक्ष्य वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी से हटाना है। उधर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने के बाद ममता ने कहा, भवानीपुर के लोगों ने नंदीग्राम की साज़िश का जवाब दे दिया है। महज 57

ममता के लिए इस जीत के क्या मायने हैं?

भवानीपुर का उपचुनाव कई मायनों में अहम था। अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव में अपने पूर्व सहयोगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी से नंद्रीग्राम सीट हारने के बाद ममता के लिए यह वजूद की लड़ाई थी। दूसरी तरफ यह चुनाव ममता और भाजपा के बीच एक तरह की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी। ममता के लिए मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। वहीं भाजपा की कोशिश थी कि यहां भी ममता को मात देकर उनके बढ़ते सियासी कद को छोटा किया जाए। साल 2011 से 2019 के बीच जो चुनाव हुए, उसमें भाजपा लगातार यहां मजबूत होती और टीएमसी का वोट शेयर घटता गया। 2011 में ममता यहां 54 हजार वोटों के अंतर से जीती थीं, लेकिन 2016 में यह कम होकर 25 हजार पर आ गया। वहीं 2011 में भाजपा को इस सीट पर केवल 5078 वोट मिले थे, लेकिन 2014 में पार्टी को 47 हजार वोट मिले थे। इस बार तृणमूल कांग्रेस ने इस बार वोट शेयर बढ़ाने के लिए खास रणनीति तैयार की थी।

फीसदी मतदान के बावजूद उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल को करीब 59 हजार वोटों के अंतर से पराजित कर दिया है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए नाक का सवाल बन गया था। दरअसल, भवानीपुर में सवाल कभी यह नहीं रहा कि ममता जीतेंगी या नहीं। यहां सबसे बड़ा सवाल था कि वे कितने वोटों के अंतर से जीतेंगी? इससे पहले वर्ष 2011 में हुए उपचुनाव में यहां वे करीब 54 हजार वोटों से जीती थीं। वर्ष 2016 में उनकी जीत का अंतर करीब 25 हजार था जबकि इस साल अप्रैल में हुए चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चटर्जी ने करीब 29 हजार वोटों से जीत हासिल की थी। इससे साफ़ है कि अबकी जीत का अंतर दोगुने से ज्यादा है। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि अप्रैल-मई में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनको हराने की साजिश रची थी। इसलिए वे चुनाव हार गईं। भवानीपुर के अलावा मुर्शिदाबाद जिले के दो सीटों जंगीपुर और शमशेरगंज में भी 30 सितंबर को उपचुनाव हुआ था। जंगीपुर में वाममोर्चा उम्मीदवार के निधन की वजह से बीते अप्रैल में मतदान स्थगित हो गया था। शमशेरगंज में भी कांग्रेस उम्मीदवार की मतदान से पहले ही मौत हो गई थी। इन दोनों सीटों पर भी टीएमसी अपने प्रतिद्वंद्वियों से जीत गए हैं। जंगीपुर लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ रहा था। बीच में वाममोर्चा के घटक आरएसपी का भी कुछ समय तक इस सीट पर कब्जा रहा, लेकिन वर्ष 2016 में तृणमूल कांग्रेस के जाकिर हुसैन की जीत के साथ यहां पार्टी का खाता खुला था।

राजनीतिक राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भवानीपुर सीट से ममता की जीत पर कोई संदेह नहीं था। बीजेपी खुद को मुकाबले में जरूर बता रही थी लेकिन नतीजों से साफ हो गया है कि कौन कितने पानी में है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं ममता इस सीट पर भारी अंतर से जीत कर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक कड़ा संदेश देना चाहती थीं। उन्होंने कहा भी है कि यह खेल भवानीपुर से शुरू होकर केंद्र की जीत पर ही खत्म होगा।

भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए नाक का सवाल बन गया था। दरअसल, भवानीपुर में सवाल कभी यह नहीं रहा कि ममता जीतेंगी या नहीं। यहां सबसे बड़ा सवाल था कि वे कितने वोटों के अंतर से जीतेंगी? इससे पहले वर्ष 2011 में हुए उपचुनाव में यहां वे करीब 54 हजार वोटों से जीती थीं।

टीएमसी अन्य राज्यों में अपने पदचिन्हों को विस्तार देने के क्रम में लगी हुई है, लेकिन कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि सीएम के भतीजे के खिलाफ ईडी का मामला उनकी इस आक्रामकता को कुछ हद तक सीमित कर सकता है। आने वाले दिनों में आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और इसकी सुप्रीमो ममता बनर्जी की क्या भूमिका होगी, इसका एक खाका उनके भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिला था। जब वे अनिर्वाचित मुख्यमंत्री विधायक बनने और नबन्ना में अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने की खातिर चुनाव लड़ रही थीं।

ममता बनर्जी का अपने घरेलू मैदान भवानीपुर में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल के खिलाफ जबर्दस्त तरीक़े से जीतना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसने पश्चिम बंगाल में उनके दबदबे में कोई इजाफा नहीं किया है, क्योंकि वे पहले से ही यहाँ की सबसे प्रमुख

राजनीतिज्ञ हैं और अपनी पार्टी के मामलों को चलाने और मुख्यमंत्री की भूमिका में कार्य कर रही हैं। प्रासंगिक प्रश्न यह बना हुआ है कि क्या यह जीत और मुर्शिदाबाद में जंगीपुर और शाशेरगंज में दो अन्य उपचुनावों में टीएमसी के उम्मीदवारों को मिली इस जीत से, देश भर में गैर-भाजपा स्थान को अपने पक्ष में हासिल करने की उनका क्षमता बढ़ने जा रही है या नहीं?

कांग्रेस भी बनर्जी को टीएमसी के पदचिन्हों को विस्तारित करने का अवसर प्रदान करती है। आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम होने के बावजूद, यह पार्टी अभी तक पश्चिम बंगाल-आधारित ईकाई ही बनी हुई है और चुनाव के मौके पर इसके कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की हिमाकत ने इसे अभी तक कोई फायदा नहीं पहुंचाया है।

इसलिए बनर्जी के लिए भाजपा विरोधी स्थान पर खुद को एक स्वीकार्य राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभारने के लिए टीएमसी को अपने पदचिन्हों को विस्तारित करने की आवश्यकता है। यह इसके गंतव्य गोवा मुहिम को व्याख्यायित करता है। इसके कुछ नेता तो पहले से ही सुझा रहे हैं कि टीएमसी को गोवा में अकेले ही पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री लुइज़िन्हो फलेरियो के नेतृत्व में भाग लेना चाहिए और सभी 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। वहां पर जल्द ही एक टीएमसी कार्यालय खुलने जा रहा है। हाल ही में टीएमसी सुप्रीमो ने यह भी संकेत दिया था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी।

इस बीच, अभी तक कुछ राजनीतिक हलकों में जो संभावनाएं दिख रही हैं। अगर बनर्जी कुछ अन्य राज्यों में टीएमसी के पैर जमा पाने में सक्षम रहती हैं और कुछ गैर-भाजपा दलों के बीच में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा पाने और साथ ही कांग्रेस को कुछ और कमजोर कर पाने में सफल रहती हैं तो हो सकता है कि बाद में वे एक बार फिर से गठबंधन के लिए वामपंथ की ओर मुड़ें। लेकिन कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस संभावना को दरकिनार कर दिया है। क्योंकि, कई राज्यों में अपनी सार्थक उपस्थिति को स्थापित कर पाना बहुत ही अधिक समय लगाने वाली कवायद है। कांग्रेस की ताकत में काफी हद तक सेंध लगने के बावजूद यह एकमात्र दल है जिसकी अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति बनी हुई है। लोकसभा की कुल 545 सीटों में से 200 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवारों को उतार सकती है।

पर्यावरण सुरक्षा को बनायें नागरिक धर्म

अवनीश सोमकुवर

हम सब अपने पर्यावरण के प्रत्येक तत्व को नमन करें जो सदा से स्पंदनशील हैं। नन्हें पौधे-विशाल वृक्ष, नन्हें झरने-विशाल नदियाँ, नन्हे कंकर-विशाल पर्वत। कीट-पतंगे और मनुष्य। सभी को नमन करने और उनकी उदारता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है आज।

वैसे पर्यावरण दिवस हर साल मनाते हैं। हर साल कुछ रस्म अदायगी होती है। चिंताएँ जाहिर होती हैं। पर्यावरण के अस्तित्व पर चर्चाएँ होती हैं। चिंता यह है कि पर्यावरण से जुड़े विषय हमारी नागरिक संस्कार से गहरे नहीं जुड पा रहे हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या नदियों को शुद्ध और जीवित रखने के मुद्दे हों या पेड़ों को बचाने का मामला हो। हमारा जुडाव गहरा होना चाहिए था।

वर्षो पहले अंग्रेजी के महान प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्डसवर्थ ने कहा था कि प्रकृति को अपना शिक्षक बनने दो। प्रकृति हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन हर हाल में खुशहाल बन सकता है। सह-अस्तित्व प्रकृति की सबसे बड़ी सीख है। इमली कभी महुआ से नहीं कहती मेरे सामने क्यों उग आये अपनी पैनी चोंच से पेड़ के मोटे तने में छेद करने वाले कठफोड़वे को पेड़ कोई सजा नहीं देता।

हाल में जर्मन वनस्पति विज्ञानी और

अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक पीटर होलबेन की किताब दि हिडन लाइफ आफ ट्रीज के कुछ अंश पढ़ने में आये। अब यह साबित हो चुका है कि पेड़ आपस में संवाद करते हैं। उनकी कोई लिपि नहीं होती। वे गंध के माध्यम से अपने संदेशों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। वे दुखी होते हैं और खुशियाँ भी मनाते हैं। अनुसंधानों से यह भी सिद्ध हो गया है कि जो पेड़ अपने सजातीय पेड़ों के बीच रहते हैं उनकी आयु लंबी होती है।

हर साल जुलाई का महीना आता है और पर्यावरण बचाने का दिखावा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अखबारों में पौधा-रोपण करते हुए चित्र छपते हैं। पौधा-रोपण का समय खत्म होते ही फिर कोई नहीं पूछता कि जिस पौधे को रोपा गया था, वह किस हाल में है। जब पौधों को बचाने की असली जिम्मेदारी आती है, तो साफ बच जाते हैं। इसीलिये जितनी संख्या में पौधे रोपे जाते हैं, बहुत कम जीवित रहते हैं।

हमारी भारतीय संस्कृति में पौधों का रोपण शुभ कार्य माना गया है। भारतीय उपासना पद्धति में वृक्ष पूजनीय है, क्योंकि उन पर देवताओं का वास माना गया है। गौतम बुद्ध का संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को पाँच वर्षो के अंतराल में एक पौधा लगाना चाहिये।

भरत पाराशर स्मृति के अनुसार जो व्यक्ति पीपल, नीम, बरगद और आम के पौधे लगता है और उनका पोषण करता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वृक्षायुर्वेद का उल्लेख है।

वर्तमान समय में पर्यावरण के प्रति जन-चेतना अवश्य बढ़ी है लेकिन महानगरीय समाज पेड़-पौधों के साथ अभी भी आत्मीय संबंध स्थापित नहीं कर पाया है। इतिहास बताता है कि पर्यावरण संवर्धन में यदि भावनात्मक प्रखरता की कमी होती है तो परिणाम नहीं निकलता।

स्वस्थ पर्यावरण की सभी को समान रूप से जरूरत है चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल या विचारधारा के हों। ऑक्सीजन के बिना जीवन नहीं होगा।

विनाश से बचने के लिये समाज को प्रकृति-आराधना की परंपरा पुनर्जीवित करते हुए वृक्षों के साथ जीना सीखना होगा।

नई पीढ़ी को नीम, आँवला, पीपल, बरगद, महुआ, आम जैसे परंपरागत वृक्षों की नई पौध तैयार करने की अवधारणा समझाना आवश्यक है। वनस्पतियों का जो सम्मान भारत भूमि पर है वह अन्यत्र नहीं है।

पाश्चात्य विद्वानों, दार्शनिकों ने भी प्रकृति का आदर करना भारतीय धर्मग्रंथों और परंपराओं से ही सीखा है। प्रसिद्ध अमेरिकी निबंधकार और दार्शनिक कवि सर इमर्सन ने अपने शिष्य हेनरी डेविड थोरो को कहा था कि यदि प्रकृति के अलौकिक स्पंदन और माधुर्य को अनुभव करना हो तो उसकी शरण में रहो।

हमारे सभी धार्मिक, सांस्कृतिक संस्कारों में वृक्षों की मंगलमय उपस्थिति है। कई भारतीय संस्कारों, व्रतों, त्यौहारों के माध्यम से वृक्षों की पूजा-अर्चना होती है। वृक्षों के नाम से कई व्रत रखे जाते हैं जैसे वट सावित्री व्रत, केवड़ा तीज, शीतला पूजा, आमला एकादशी, अशोक प्रतिपदा, आम्र पुष्प भक्षण व्रत आदि। मनु स्मृति में वर्णित है कि वृक्षों में चेतना होती है और वे भी वेदना और आनंद का अनुभव करते हैं। समाज के गैर जिम्मेदार व्यवहार से यदि उनकी मृत्यु होती है तो समाज को उतना ही दुःख होना चाहिये जितना प्रियजन की मृत्यु पर स्वाभाविक रूप से होता है।

समाज की ओर से भी पौधा रोपण का स्वैच्छिक अनुष्ठानिक कार्य होना चाहिये। भविष्य की पीढ़ी अपने पुरखों पर गर्व कर सके इसके लिये वर्तमान पीढ़ी से थोड़ी-सी संवेदनशीलता की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व-प्रेरणा से हर दिन एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। यह उनके नागरिक संस्कार को प्रोत्साहित और आम नागरिकों को प्रेरित करने की अनूठी पहल है। यदि प्रत्येक नागरिक एक जीवित नन्हे पौधे का जिम्मेदार और संवेदनशील पालक बनने की चुनौती स्वीकार कर लें तो हम सब हरियाली से समृद्ध होते जायेंगे। इसलिये आज यह संकल्प लें कि हम जहाँ रहें अपने पर्यावरण का आदर करें।

वैक्सीन की प्रथम डोज आंशिक सुरक्षा, दूसरी डोज मतलब पूरी सुरक्षा

जी.एस.वाधवा

कोरोना महामारी के विरूद्ध पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए वैक्सीनेशन काफी कारगर साबित हो रहा है। वैज्ञानिक तथ्य भी यही कहते हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज समय पर लग जाने से व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की संभावना 93 प्रतिशत तक घट जाती है। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों की मृत्यु की संभावना भी नगण्य हो जाती है। प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये संवेदनशील राज्य सरकार लक्षित समूह को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देने के लिए कटिबद्ध है। वैक्सीनेशन का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर 25 एवं 26 अगस्त को दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा।

कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर ने विश्व के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में ले लिया था। कोरोना काल में अनेकों ने अपनी जान भी गंवाई। कोरोना के साथ लड़ाई में भारत ने कम समय में स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर एक अनूठा उदाहरण पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। वैक्सीन का निर्माण जितनी तेजी से किया गया, उतनी ही रफ्तार से प्रदेशों में वैक्सीन पहुँचाई भी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सबको वैक्सीन-निःशुल्क वैक्सीन मंत्र देकर वैक्सीन तक सभी की

पहुँच सुनिश्चित की। वैक्सीन की उपलब्धता के साथ उसके उपयोग में मध्यप्रदेश पूरे राष्ट्र में अग्रणी रहा।

वैक्सीन के द्वितीय डोज का महत्व

कोरोना महामारी से बचाव के तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कोविड-19 के दोनों डोज लगवाना अत्यन्त आवश्यक है। कोविड-19 टीके का प्रथम डोज मनाव शरीर में आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके लगने के बाद भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। वैक्सीन का द्वितीय डोज समयावधि में लगवाने से वैक्सीन की एफिकेसी सर्वाधिक रहती है। प्रदेश में अभी दो प्रकार की वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है। चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम डोज लेने के 84 दिन बाद द्वितीय डोज और कोवैक्सीन की प्रथम डोज लेने के 28 दिन बाद द्वितीय डोज लेना जरूरी है। वैक्सीन की द्वितीय डोज लगने के 2 से 3 सप्ताह बाद ही शरीर में कोरोना बीमारी के विरूद्ध प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होती है। साथ ही शरीर एक से अधिक प्रकार की एंटीबॉडी तैयार करता है जो कोरोना और उसके अन्य वेरिएंट के विरूद्ध बचाव करने में सहायक होती है।

महाअभियान को सफल बनाने जन-भागीदारी भी जरूरी

कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की जिम्मेदारी भी है। हर नागरिक को स्व-प्रेरणा से आगे आकर सरकार द्वारा दिए जा रहे वक्सीन के सुरक्षा कवच को अपनाना होगा। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए चलाए गए प्रथम टीकाकरण महाअभियान में राष्ट्रीय स्तर पर जो सफलता मिली, उसमें जन-भागीदारी की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण 25 एवं 26 अगस्त को होने जा रहा है। प्रथम महाअभियान की तरह इस महाअभियान में भी राज्य सरकार के प्रयासों के साथ जनता की भागीदारी भी बहुत जरूरी होगी।

वैक्सीनेशन के बाद भी सजग और सर्तक रहना है जरूरी

यूं तो वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवा लेने के बाद काफी हद तक कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हो जाता है। इसके बावजूद भी सजग और सर्तक रहने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस के प्रति अनुकूल व्यवहार को अपनाते रहना होगा, जिसमें मास्क लगाना, हाथों को समय-समय पर सेनेटाइज करना, ज्यादा भीड़-भाड़ न करना और न ही उसमें शामिल होने जैसी गतिविधियों को अपनाते रहना होगा। तभी हम अपने आपको और समाज को कोरोना वायरस से बचा पाएंगे।

नागरिकों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील सरकार

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिये जो भगीरथी प्रयास किये वह किसी से छिपे नहीं हैं। कोरोना की जाँच से लेकर उपचार की जो व्यवस्थाएँ की गई, उससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हर नागरिक को मिल जाए, यह प्रयास राज्य की संवेदनशील सरकार ने किया है। इन प्रयासों में आम नागरिक के साथ धर्मगुरूओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, कोरोना वॉलेंटियर्स, शहरी-ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों के साथ समाज के हर वर्ग को आगे आकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ वैक्सीनेशन महाअभियान में सहयोग करना होगा।

प्रदेश में 4 करोड़ के पार हुआ वैक्सीन डोज का आंकड़ा

वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर यदि नजर डाले तो हम पायेंगे कि मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए लक्षित समूह की संख्या 5 करोड़ 49 लाख है, जिसके विरूद्ध अब तक प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें से वैक्सीन की दूसरी डोज 65 लाख से अधिक लोगों को लग चुकी है। वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने के लिये मध्यप्रदेश में टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण 25 अगस्त से प्रांरभ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वैक्सीन के दूसरे डोज का कव्हरेज बढ़ाना भी है।

संकल्प के साथ जिंदगी जी रहे वृक्षमित्र सुनील दुबे

समता पाठक

वृक्षमित्र सुनील दुबे आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने जीवन के कई उतार-चढ़ाव के बीच आज उन्होंने अपने आपको इस तरह स्थापित किया है कि वह कई लोगों के लिए प्रेरणास्त्रोत बन गए हैं। जिंदगी और मौत की खाई को पाटते हुए आज वह एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें संकल्प है, सेवाभाव है और संदेश है। दृढ़ इच्छा शक्तिव और आत्म विश्वास से भरपूर और मौत को मात देने वाले सुनील दुबे की जिंदगी में एक समय ऐसा मोड़ आया था जिसने उन्हें अंदर से टूटने पर मजबूर कर दिया था लेकिन हार न मानने वाले सुनील दुबे ने अंतिम समय में एक ऐसा संकल्प लिया, प्रण लिया जिससे उन्हें जीने का मकसद मिला। बात 8 जुलाई 2008 की है। जब उन्हें पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इस

बात का पता चलते ही स्वयं के साथ-साथ उनके परिवार वालों को अंदर से झंकझोर दिया। ईलाज के लिए मुंबई के बाम्बे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों का कहना था कि ब्रेन ट्यूमर में 05 गुना अधिक रक्त प्रवाह कर रहा है। आपरेशन करने पर शरीर का सारा रक्त बाहर निकल जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। तब मैंने डॉक्टरों से कहा था, मरने वाला नहीं हूं, अपाहिज भी नहीं होने वाला हूं। आप आपरेशन कीजिए। ट्यूमर पेपरवेट से थोड़ा ही छोटा था। आपरेशन थियेटर में जाने से पहले मैंने संकल्प लिया कि यदि मैं बच गया और स्वस्थ्वाल रहा तो अगला जीवन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित करूंगा। जितना वेतन मिलेगा समाजसेवा और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ औषधीय पौधों की वर्कशॉप लेने में, चरक संहिता का अधिक अध्ययन करने में लगाऊंगा। सुनील दुबे का ऑपरेशन सफल रहा और बहुत जल्द वह स्वस्थ्य भी हो गये। 17 सितंबर 2008 से ही उन्होंने पौधे बांटना और लगाना शुरू कर दिया। आज वह भारत के पांच राज्यों में पौधे लगवा रहे हैं। अब तक 03 लाख 25 हजार 912 पौधे लगवा चुके हैं और लोगों को 04 लाख से अधिक पौधे बांट चुके हैं। उनके द्वारा विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति के पौधों के अलावा फलदार, छायादार पौधों के साथ-साथ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, पीपल, नीम, आंवला, महुआ, हरण बहेड़ा, पीले पलाश, पीला धतूरा आदि रोपित किए जा रहे हैं। उन्होंने बस्तियों में वृक्षों को कटने से बचाने के लिए वृक्ष रक्षक दल बनाया है और प्रतिदिन 05 पौधे लेकर घर से सुबह निकल जाते हैं और किसी को भी यह पौधे दे देते हैं। ताकि इन पौधों को रोपा जा सके। इन्हें पेड़ों से इतना प्रेम है कि आज भी जहां पेड़ पर कील मिलती है, उसे निकालते है।

छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल को बचाने के लिए भी वह अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि बक्सवाहा के जंगल को हीरे की खदान खोदने के लिए एक कंपनी को दिया गया है। जिससे इस जंगल के करोड़ों पेड़ों का काटा जाना है। जंगल बचाने की इस मुहिम में सुनील दुबे भी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो बक्सवाहा को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

मनुष्य की प्रवृत्ति और पलायनवादिता

मणिशंकर पाण्डे

आदि मानव काल से ही मनुष्य का विकास सतत रूप से हो रहा है और आधुनिक समय चीख-चीख कर मनुष्य के विकास की गाथा गा रहा है। मानव हमेशा से ही एक स्थान से दूसरे पर आवागमन करता रहा है। कभी आसपास के क्षेत्र में तो कभी समन्दर पार। कभी अकेले और कभी सामूहिक रूप से प्रवास से ही मानव विकास का वर्तमान विकसित रूप से उभर कर सामने आया है। मनुष्य अपनी जीविका परिस्थिति व व्यक्तिगत सामंजस्य आधार पर अपना आवास सुनिश्चित करता था परंतु सभ्यता जैसे-जैसे विकसित हुई मानव ने आवश्यकताओं और अन्य दूसरे कारणों से लगातार पलायन किया है और यह पलायन आज भी जारी है। यूं कहें की मनुष्य की प्रवृत्ति ही पलायनवादी है। या यूं कि आज के मनुष्य का विकास मनुष्य की प्रवासी प्रवृत्ति के कारण ही संभव हो सका है। प्रवास की प्रवृत्ति आज के समय में कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वर्तमान में कुछ मराठी नेताओ का का यह मानना है कि उत्तर भारतीय जो मुंबई महाराष्ट्र में बाहरी लोग है। वह देश के लिए एक कठिन स्थिति पैदा कर रहे है। घर और बाहर के लोगों का यह संघर्ष राजनैतिक खेमों में जाकर मुद्दे का रूप ले रहा है एवं राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ तुच्छ और संकीर्ण सोच वाले नेताओं की सरपरस्त में सुलग रहे है। अलग-अलग कबीलों, संस्कृतियों, देशों और सभ्यताओं के बदलाव और विकास में मानव का प्रवास एक बड़ा कारक रहा है।

आज के समय में मनुष्य अच्छे जीवन स्तर के लिए या फिर मजबूरी से पलायन कर रहा है। भोजन, आवास और सुरक्षा प्रारंभ से ही मनुष्य के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और इसी के लिए मुनष्य पलायन करता है अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाये तो मानव के प्रवास करने की प्रवृत्ति दर्ज है।

ग्लोबल कमीशन ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन की 2005 में पेश की गई रिपोर्ट में मानव प्रवास के विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया गया है। पलायन की कई श्रेणिया होती है जैसे रोजगार के लिए दैनिक

यात्रा, कृषि के लिए ऋतुओं के आधार पर प्रवास लंबे समय तक के लिये ये स्थायी प्रवास, स्थानीय, क्षेत्रीय, विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण के कारण गांवों में शहरों की ओर तथा विकसित देशों में रहन सहन महंगा होने से गांवों की ओर पलायन एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ये सभी पलायन-प्रवास की कुछ श्रेणियां है। 18वी सदी के बाद विश्वभर में औद्योगिक क्रांति के आने से पलायन वादी प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ है। अंग्रेजों ने विश्व भर में उपनिवेश बनाए थे तभी से मजदूरों का पलायन आज तक सतत रूप से चल रहा है। आजादी के पश्चात पंजाब से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कनाडा, इंग्लैंड अमेरिका आदि देशों में बेहतर भविष्य की आस में प्रवास कर रहे हैं लोग अच्छे जीवन के लिए प्रवास पर जाते तो है परंतु पीछे अवसाद ग्रसित परिवार छोड़ जाते हैं साथ ही साथ जहां पर वह आवास या रोजगार के लिये जाते है वहां के लिए विषम समस्या खड़ी कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉ. गिरीश्वर मिश्र के अनुसार प्रवास पर व्यक्ति को परिवार या समूह के साथ-साथ नए स्थान या क्षेत्र से तालमेल बैठाना पड़ता है पर्यावरण व खानपान आदि को अपने अनुरूप बनाना पड़ता है। फिर यह भी समस्या रहती है कि नए स्थान के लोग या समूह उसे कितना स्वीकार या अस्वीकार करते है। यही परिस्थितियां उसके प्रवास को सफल या असफल बनाती है। एवं अपनी पहचान कायम रखते हुए उसे उनके जैसा दिखना पड़ता है कई बार इस बदलाव में व्यक्ति अपनी वास्तविक छवि को भी खो बैठता है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बड़ी समस्या का सामना उसे लगातार करना पड़ता है। पीढियों पहले प्रवास कर चुके लोगों की तुलना में हालिया प्रवास करने वाले स्थानीय और बाहरी जैसे संघषों में निशाना बन जाते है। निजी लोगों को सदा यह बात खलती है कि बाहरी लोग हमेशा से उनके एक बड़े हिस्से को चट कर जाते है। इसमें पलायन वादिता पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है मगर नियंत्रण नहीं लेकिन प्रवास को रोकना अपनी आप में एक बहुत बड़ा अपराध होगा क्योंकि कभी-कभी व्यक्ति महौल से इतना अवसाद ग्रसित हो जाता है कि उसका अपने गंतव्य स्थान पर निवास करना मुमकिन नहीं होता है इस कारण से उसे पलायन करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में अपने पराए के संघर्ष में अपना भले ही खराब हो पराए से हमेंशा अच्छा लगता है। डॉ. मिश्र के अनुसार ऐसे दोनों समूहों को उनकी अनुपूरता के महत्व के बारे में बताने के लिए सजगता परम आवश्यक है। ऐसे में राजनैतिक व सामाजिक स्तर पर देशहित मानवहित को महत्व देना चाहिए। ताकि छोटे स्वार्थ बड़े महत्व पर हावी न हो जाए। दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो हर हाल में अपना मुल्क अपना वतन अपनी जमीं को छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्योंकि पलायन में व्यक्ति के जीने की संभावना व कुछ कर गुजरने का जुनून छिपा होता है। जिस कारण से प्रवास का अपना अहम महत्व है।

कितना दुरूह है मरूस्थल का जीवन

डॉ. डी.डी. ओझा

मरूस्थल शब्द का उच्चारण करते ही एक जल रहित, तीव्र झुलसने वाला, वायु द्वारा निघर्षित तथा दूर-दूर तक छायाहीन व वनस्पति रहित क्षेत्र सजीव हो जाता है। अर्थात वहां दूर-दूर तक रेत ही रेत दिखलाई देती है। कहीं-कहीं पर छोटी-छोटी झाड़ियां तथा कटीले सूखे, पत्तियों रहित वृक्ष क्षेत्र की अनुवर्रता को चुनौती देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। वस्तुतः मरूस्थल का शाब्दिक अर्थ है मृत भू-भाग। अर्थात् वह भू-भाग जिसमें सतही जल का अभाव हो। इसके साथ ही वहां की मिट्‌टी में जैविक तत्वों एवं नमी का अभाव हो। जलवायु की दृष्टि से पृथ्वी पर मरूस्थल ऐसे क्षेत्र होते है, जहां भू-भाग से वर्षण की अपेक्षा अत्यधिक वाष्पन होता है। जिसके कारण मृदा अथवा वायु में विद्यमान नमी किसी भी वनस्पति की वृद्धि के लिए अपर्याप्त रहती है।

विश्व में सर्वप्रथम वर्ष 1918 में ऑस्ट्रिया के डा. ब्लादीमीर कोपेन ने बताया कि विश्व के 1456 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग का 28 प्रतिशत क्षेत्र 250 मिलीमीटर से कम वर्षा वाला तथा 14 प्रतिशत 250-500 मिलीमीटर वर्षा वाला शुष्क क्षेत्र है। मरूस्थलों की प्रकृति तथा मरूस्थलीकरण के कारणों के अध्ययन के नैरोबी में वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में विश्व के संपूर्ण मरूप्रदेश के लिए एक मानचित्र तैयार किया गया जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के 75 प्रतिशत, अफ्रीका के 34 प्रतिशत एशिया के 31 प्रतिशत अमेरिका के 19 प्रतिशत और यूरोप के 2 प्रतिशत भाग में रेगिस्तान के प्रसार का संकट व्याप्त है।

मुख्य रूप से मरूस्थल या रेगिस्तान दो प्रकार के होते है - गरम व ठंडे। राजस्थान का रेगिस्तान गरम तथा अंतःस्थलीय प्रकार का है। किसी स्थान या क्षेत्र को कितनी मात्रा में वर्षा का जल प्राप्त होता है के अधार पर भारतीय रेगिस्तान को मुख्य रूप से शुष्क तथा अर्द्ध-शुष्क दो भागों में विभक्त किया गया है। हमारे देश का 12.13 प्रतिशत क्षेत्रुल अर्द्धशुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

राजस्थान प्रदेश में मरूभूमि का क्षेत्रफल 1.91 लाख वर्ग किलोमीअर है जो देश की कुल मरूभूमि का 61 प्रतिशत है। विशेष

रूप से राजस्थान में मरूस्थलीय क्षेत्र के 12 जिले इससे सर्वाधिक प्रभावित हैं। गुजरात व कच्छ का मरूस्थल भी एक विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में गर्मियों में तपती धूप एवं गरम रेत के कारण तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तथा शीतकाल में तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 37.5 सेंटीमीटर है तथा वायु का औसत वेग 16 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होता है। राजस्थान में रेत के टीलो की लंबाई 100 मीटर से भी अधिक तक देखी गई है। गरमी के मौसम में जब भीषण गरमी पड़ती है तब इन क्षेत्रों में तेज आंधियां चलती है जिससे रेत के टीलों का स्थानांतरण समतल मैदानी क्षेत्रों में हो जाता है, फलतः संपूर्ण जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है।

मरूस्थलीकरण संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की एक प्रमुख समस्या है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पुरानी दुनिया के अधिकांश रेगिस्तान मानव निर्मित है अर्थात उनके बनने मे मुनष्य के विनाशकारी क्रियाकलाप विशेष रूप से उत्तरदायी है। जलवायु तो केवल ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिनके परिणाम स्वरूप ये परिवर्तन संभव होते हैं।

हमारे देश में राजस्थान का थार मरूस्थल महान भारतीय मरूस्थल के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः मरूस्थल कठिनता तथा न्यूनता वाले क्षेत्र होते हैं, फिर भी यहां के मानव समुदाय ने यहां की परिस्थिति के अनुरूप एक ऐसी जीवन शैली एवं विकास की पद्धति को विकसित कर अपनाया जिसमें सादा जीवन, कम आवश्यकताएं, प्रत्येक वस्तु का सही तथा पूरा उपयोग, स्थानीय पर्यावरण एवं प्रकृति के साथ लगाव का समावेश है। विश्व के सभी मरूस्थलों की अपेक्षा थार रूक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। अर्थात 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि विश्व के अन्य रेगिस्तान में आबादी मात्र 3-5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। मरूभूमि का परितंत्र भी बहुत विचित्र है। तथा अपनी अनोखी शान भी रखता है। दिन के समय ग्रीष्मकाल में प्रचंड

ताप तथा रात्रि के तापमान में तेज गिरावट, वायुमंडल की कम आर्द्रता, कम एवं अनियमित वर्षा तथा धूल भरी आंधियां यहां के पेड़-पौधें तथा मानव को भी वातावरण के अनुरूप जीवन व्यतीत करने को बाध्य कर देती है। मरूक्षेत्रों में अपर्याप्त सतही जल स्त्रोतों के कारण भू-जल ही एक मात्र पीने तथा सिंचाई का साधन है।

मरू क्षेत्रों में भू-जल भी बहुत गहराई पर मिलता है। जो लवणीय होता है तथा कई क्षेत्रों में नाइट्रेट एवं फ्लाराइड युक्त है। थार मरूस्थल का प्राणीजगत चाहे पशु-पक्षी या मनुष्य समाज हो, कठोरतम परिस्थितियों में रहने का अनोखा सामर्थ्य रखते है ऐसा ही यहा की वनस्पतियों के बारे में कहा जा सका है। यही कारण है कि सदियों से पड़ने वाले सूखे तथा अकालों के बाद भी यहां जीवन विद्यमान है, जीवंतता बनी हुई है। विषम जलवायवीय स्थिति के कारण यहां की वनस्पतियों में कुछ निम्नवत अनुकूलन विकसित हुए है -

- सभी झाडियों तथा वृक्षों के तने या तो गूदेदार होते है, जिससे जल का भंडारण हो सकता है तथा ग्रीष्मकाल में जल आपूर्ति भी हो सकती है अथवा तनों पर मोटी छाल लगी रहती है जिससे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति रोगी जा सकती है।

- मुरू क्षेत्र की कई झाड़िया तथा घास लवणव सहनशील होती है तथा ये लवणीय जल में भी पनप सकती है।

- मरूस्थल के कई जानवरों का मल शुष्क एवं गुटिका के रूप में होता है। यह भी जल संरक्षण का एक उपाय है। इसी तरह मरू क्षेत्रों के कई की नाईट्रोजनीय अपशिष्ट के रूप में मल निष्कासित करते है जो अन्य जानवरों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है।

- मरूस्थलीय कीटों का छदमावरण भी एक विशिष्ट लक्षण होता है। इसी तरह कई प्रकार के कीट मौसम की विषमताओं को झेलने में समर्थ होते हैं, यहा - टिड्डी की अंडजोत्पति दो-तीन वर्ष पश्चात भी हो सकती है। जब वर्षा पर्याप्त होती है तथा घास की संघनता होती है।

अतः यह कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि थार मरूस्थल का जीवन अलमस्ती वाला भी है तथा विश्व के सभी मरूस्थलों के प्राणी एवं वनस्पति जगत की दृष्टि को देखते हुए यह बहुत उत्पादकता वाला भी है। विकट जलवायवीय स्थितियों के बावजूद इस मरू भूमि में शिल्प तथा स्थापत्य की अनूठी भवन निर्माण कला का विकास हुआ है। यहां के लोग विपरीत जलवायु व प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए भी गरिमा एवं शान को कभी नहीं छोड़ते है। मरू भूमि ने अपनी कोख से अनेक शूरवीर, दानवीर, संत एवं वैज्ञानिक उत्पन्न कर अपने आपको गौरवान्वित किया है।

प्रदूषण का शिकार सारा जगत

प्रियंका पटनायक

वर्तमान समय में पृथ्वी का तापमान बढ़ना भविष्य के अनेक खतरों की और इशारा करता है। और यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि प्रकृति हमें आने वाले विकराल खतरों से हमें आगाह कर रही है। जो हड़बड़ी में फंसे मानव समुदायों के क्रिया कलापों का नतीजा है। आज हमारी पृथ्वी जिस विनाश की ओर जा रही है उसके लिए अति औद्योगिकीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारवाद और उपभोगतावादी प्रवृत्ति ही जिम्मेदार है। आज प्रकृति का जितना दोहन मानव सुविधाओं हेतु हुआ है उतना कभी भी नहीं देखा गया है। एवं ओजोन परत भी लगातार क्षतिग्रस्त होती जा रही है एवं ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाईआक्साइड, मीथेन तथा नाईट्रस आक्साइड आदि प्रमुख है। वे अति उत्सर्जन के कारण ही आज पृथ्वी विनाश के कगार पर है। अति विषैली गैसों के उत्सर्जन का आरोप चीन व भारत पर लगाया गया है व राष्ट्र एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे क्योंकि इस जटिल समस्या के जिम्मेदार मात्र औद्योगिक राष्ट्र ही है एवं आज जो समस्या मुंह बोये खड़ी है उससे निपटने के लिए आर्थिक व सैन्य बल कुछ नहीं कर सकते है। आज प्रकृति के अनियंत्रित दोहन का परिणाम यह निकला कि बिन मौसम वर्षा तूफान आता है और मौसम अपनी मर्जी करता रहता है। आज भारतीय गौरव हिमालय की इस प्रदूषण का शिकार हो

गया है। हिमालय एवं अन्य बर्फीले पर्वतों की वर्फ तीव्र गति से गलने लगी है एवं ग्लेशियर पीछे की ओर सरकने लगे है। ग्रीनलैंड व अंटार्कटिका की बर्फ भी तेजी से पिघलने की संभावनायें प्रकट कर रही है। और आज इन विफसल परिस्थितियों से निपटने के लिए समाज एवं सरकार जूझने को तैयार खड़ी है। पृथ्वी के सर्वाधिक दोहन करने वाले राष्ट्रों को भी अब लगने लगा है कि अब अलग से सुरक्षा व्यवस्था करना संभव नहीं है। और प्रकृति अब किसी की राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन करने में अपनी मनमानी कर सकती है। एवं हमारे वायुमंडल में इतनी अधिक कार्बन डाय आक्साइड पिछले 650000 वर्षो में कभी नहीं रही यानी इतना खतरा कभी नहीं रहा। यदि इक्कीसवी सदी में दुनिया के देशों के समझदारी के साथ ग्रीन हाऊस विषैली गैसों पर नियंत्रण नहीं लगाया तो धरती का तापमान नदी के अंत तक 4 या 5 डिग्री बढ़ने से भी संकटमय स्थिति बन सकती है। और इसके कारण मरूस्थलीकरण बढ़ेगा व पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जायेगी, जो हर प्रकार से जीव जगत व वनस्पति जगत के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। और इस विषम संकट व विषैली गैसों को निगल जाने वाले कवच का निर्माण करना परम आवश्यक है। अतः जंगलो की कटाई पर रोक लगाकर उनके विस्तार के प्रयास जोर शोर से कर देना चाहिए व नगरी व शहरी इकाइयों में भी वृक्षारोपण की प्रक्रिया को बल प्रदान करना चाहिए तब कही जाकर हम ग्रीन हाऊस प्रभाव से विश्व को बचाने की स्थिति में होगे। इसके साथ-साथ विषैली गैसो पर भी नियंत्रण लगाना चाहिए व आधुनिक तकनीक के चलते नई प्रजातियों को इजात कर प्रदूषण कम करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो संपूर्ण जीव जगत विनाश का ग्रास बन जायेगा। पवन उर्जा, सौर उर्जा को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए। और भारत जैसे देशों में इस कुठाराघात का दंश आम जनता को झेलना पड़ेगा जिसमे उनका कोई दोष नहीं होगा। और प्रदूषण युक्त औद्योगीकरण वाली प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाकर ही इस विनाश विभीषिका को रोका जा सकता है।

जिन्हें ताज मिला मगर कब्र नहीं

विनय दीक्षित

भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की शानदार कब्र समरकंद मे है। उसके पुत्र हुमायूं का आलीशान मकबरा दिल्ली में है। सम्राट अकबर का आगरा के निकट सिकंदरा स्थित मकबरा उसकी सर्व-धर्म समभाव की नीति के अनुरूप बनाया गया है। जहांगीर का भव्य मकबरा लाहौर में है। शाहजहां आगरा के 'ताजमहल' में अपनी पत्नी मुमताज महल की कब्र के समीप ही दफन है। औरंगजेब का निधन 1707 ईसवी में गुजरात में हुआ था। उसे उसकी इच्छा के अनुसार दौलताबाद के समीप खुलदाबाद में दफनाया गया। औरंगजेब की कब्र बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से बनाई गई। उस पर किसी भवन, मकबरा का गुंबद का निर्माण नहीं किया गया। बाद में गुजरात के सूबेदार ने कब्र के चारों और संगमरमर की सफेद जालियां लगवा दीं। आज भी औरंगजेब की यह कब्र वहां मौजूद है लेकिन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में कई इतने बदनसीब रहे कि उन्हें मरने के बाद कब्र तक नसीब नहीं हुई।

जफर के कई पूर्वज इतनी बेरहमी से अकस्मात मारे गये कि वे कफन-दफन के भी मोहताज रहे। मुगल बादशाह हुमायूं के भव्य मकबरे के आसपास कई ऐसी छोटी और उपेक्षित बेनाम कब्रें हैं, जिनमें कभी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुगल बादशाह दफन किये गये लेकिन मकबरे की सुंदरता को देखने वाले हजारो पर्यटकों को इन अभागे बादशाहों की कब्रो के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और न ही जानकारी देने की कोई व्यवस्था ही की गई है। बहादुरशाह प्रथम : औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सत्तासंघर्ष हुआ और इस संघर्ष में विजयी होकर उसका पुत्र मोहम्मद मुअज्जम बहादुरशाह (प्रथम) गद्दी पर बैठा। उसे शाहआलम की उपाधि औरंगजेब ने हीं प्रदान की थी। अतः बहादुशाह को शाहआलम भी कहा जाता है। उसने पांच वर्ष तक शासन किया और 70 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 1712 को उसका बीमारी के कारण निधन हो गया। उसे लालकिलें के समीप एक बगीचे में दफना दिया गया। बहादुरशाह की कब्र के बारे में लोग अनजान है। जहांदारशाह : बहादुरशाह के बाद उसके चार पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए खूनी संघर्ष हुए। बाद में 29 मार्च, 1712 को जहांदारशाह का राज्याभिषेक हुआ। वह एक नितांत अयोग्य, कमजोर, व्यभिचारी, विलासी और चरित्रहीन

शासक साबित हुआ। अपने शत्रुओं से समझौता करके वह युद्ध से बचता रहा। राज्य में बदइंतजामी और भ्रष्टाचार फैलने से सेना, राजदरबार और प्रजा में असंतोष फैलने लगा। इसी बीच दरबारी सैयद बंधुओं से मिलकर फर्रूखसियर ने जहांदारशाह की लालकिले में ही हत्या करा दी और हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया।

फर्रूखसियर : 1713 में फर्रूखसियर बादशाह बना। उसने 1719 तक शासन किया लेकिन राजपूत, सिख जाट और मराठों के लगातार विद्रोह, उत्पातों, दरबार की दलबंदी से वह परेशान रहा। शक्तिशाली सैयद बंधुओं ने बादशाह को अपनी कठपुतनी बनाने के लिए कई षडयंत्र किये और अंत में उन्होंने फर्रूखसियर को दिल्ली के लालकिले में बंदी बना लिया। 29 अप्रैल, 1719 को सैयद बंधुओं ने वधिकों से उसकी हत्या करा दी और उसके जनाजे को हुमायूं के मकबरे तक ले जाकर, वहां तहखाने में चुपचाप उसे दफन कर दिया। फर्रूखसियर भले ही कमजोर और अयोग्य बादशाह रहा हो लेकिन गरीबों, बेसहारा स्त्री-बच्चों, फकीरों, भिखारियों के प्रति सदा उदार और दयालु बना रहा। वह खुले हाथों में भिखारियों को दान दिया करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसके वजीर, दरबारी और हरम के कर्मचारी नाशुक्रे हो गये लेकिन दिल्ली के भिखारियों ने 40 दिनों तक शोक मनाया। उन्होंने फर्रूखसियर की कब्र पर जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए 40 दिनों तक शोक सभा की। बताते हैं कि दिल्ली के भिखारी प्रतिवर्ष फर्रूखसियर की मृत्यु तिथि पर शोकसभा करने उसकी कब्र पर जाते थे। और भिक्षा में मिली खाद्य सामग्री आपस में बांटकर मृत्युभोज की रस्म अदा करते थे। 1857 की सैनिक क्रांति के बाद भी बरसों तक ब्रिटिश शासनकाल में दिल्ली में भिखारियों ने इस परंपरा को जारी रखा लेकिन आज बुलंद मकबरें के तहखाने के बादशाह फर्रूखसियर की कब्र की पहचान करना मुश्किल है।

रफीउद्दरजात : फर्रूखसियर के बाद रफीउद्दरजात, 1719 में केवल चार माह के लिए बादशाह बना। क्षयरोग से पीड़ित उस बादशाह की 11 जून, 1719 को बिस्तर पर मौत हो गई। उसे एक सादे समारोह में लालकिले के पास दफना दिया गया। बीमारी में ही दरबारियों ने बादशाह के बड़े भाई रफीद्दौला को तख्त-ए-ताउस पर बादशाह बनाकर बिठा दिया। वह भी क्षयरोग से पीड़ित था। कुछ महीने बाद 17 सिंतबर, 1719 को उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी कब्र भी अज्ञात है।

बहादुर शाह 'जफर'

आखिरी नज्म

लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में।
किसकी बनी है आलम-ए-नापाएदार में।।

कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें।
इतनी जगह कहाँ है दिल-ए-दागदार में।।

उमर-ए-दराज माँग के लाए थे चार दिन।
दो आरजू में कट गए दो इंतजार में।।

कितना है बदनसीब 'जफर' दफ्न के लिए।
दो गज़ ज़मीन भी न मिली कू-ए यार में।।

(भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह 'जफर' की यह आखिरी नज्म है, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर वर्मा भेज दिया था वहीं उनकी मृत्यु और वहीं वे दफन हुए)

रंगीले बादशाह : अपने संगीत और कलाप्रेम के कारण 'रंगीले' नाम से आज भी विख्यात है। वह 1719 से 1748 तक बादशाह रहा। औरंगजेब के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले बादशाह मोहम्मदशाह के शासनकाल में मुगल सल्तनत अस्त-व्यस्त हो गई। जाट, सिख, मराठे और कई राजपूत राजा अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में सफल रहे और वे नाममात्र के लिए ही बादशाह की सत्ता को मानते थे। मुगल दरबार में सत्ता-महत्वाकांक्षा के कारण संघर्ष तेज होने लगा। नादिरशाह के हमले में बादशाह की शर्मनाम पराजय हुई। बाद में नादिरशाह से समझौता करके मुहम्मदशाह ने अपनी गद्दी बचाई लेकिन नादिर शाह मुगलों की अपार धन-दौलत और तख्त-ए-ताऊस भारत से अपने साथ ले गया। 28 वर्ष, पांच माह तक मुगल सल्तनत संभालने वाले मोहम्मदशाह का 1738 में निधन हो गया। उसके बाद उसका पुत्र अहमदशाह दिल्ली के तख्त पर बैठा।

अहमदशाह के शासनकाल में मुगल सल्तनत में बिखराब बढ़ा और बादशाह का शासन दिल्ली में दोआब तक ही सीमित रह गया। राजपूत, सिख, जाट, मराठे शक्तिशाली हो चुके थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य कायम करके उन्हें बादशाह ने मान्यता भी दे दी थी। पठान, रूहेले और अफगान भी छोटे-छोटे राज्यों के सार्वभौम सत्ताधीश बन चुके थे। मुगल दरबार में दलबंदी इतनी ज्यादा हो गई थी कि बादशाह को किसी पर विश्वास अहमदशाह और उसके वजीर सफदरजंग के बीच गृहयुद्ध चल रहा था। दिल्ली में अराजकता थी। दरबार में शक्तिशाली वजीर और सरदार सत्ता-संघर्ष में व्यस्त थे तो बादशाह भोग-विलास में मस्त था। इस माहौल में वजीर इमादउल मुल्क ने षड्यंतपूर्वक बादशाह अहमदशाह और उसकी मां उधमबाई को बंदी बना लिया और अंधा कर दिया। उनकी मृत्यु उनके दफन के बारे में कहीं कोई भरोसेमंद प्रमाण नहीं आयु में बादशाह बना था। वृद्धावस्था में वह भोग विलास में लिप्त हो गया। साठ वर्ष की आयु में उसने जिन्नत अफरोज बेगम से विवाह किया। साथ ही अपने हरम में असंख्य सुंदर लावण्यमयी विलासी स्त्रियों को दाखिल किया। आलमगीर में प्रशासन, सेना और वित्त व्यवस्था के संचालन की कोई योग्यता नहीं थी। उसने बादशाह के सभी अधिकार वजीर इमाद-उल-मुल्क को सौंप दिये थे। खाली खजाने और लालकिले के भीतर शाही

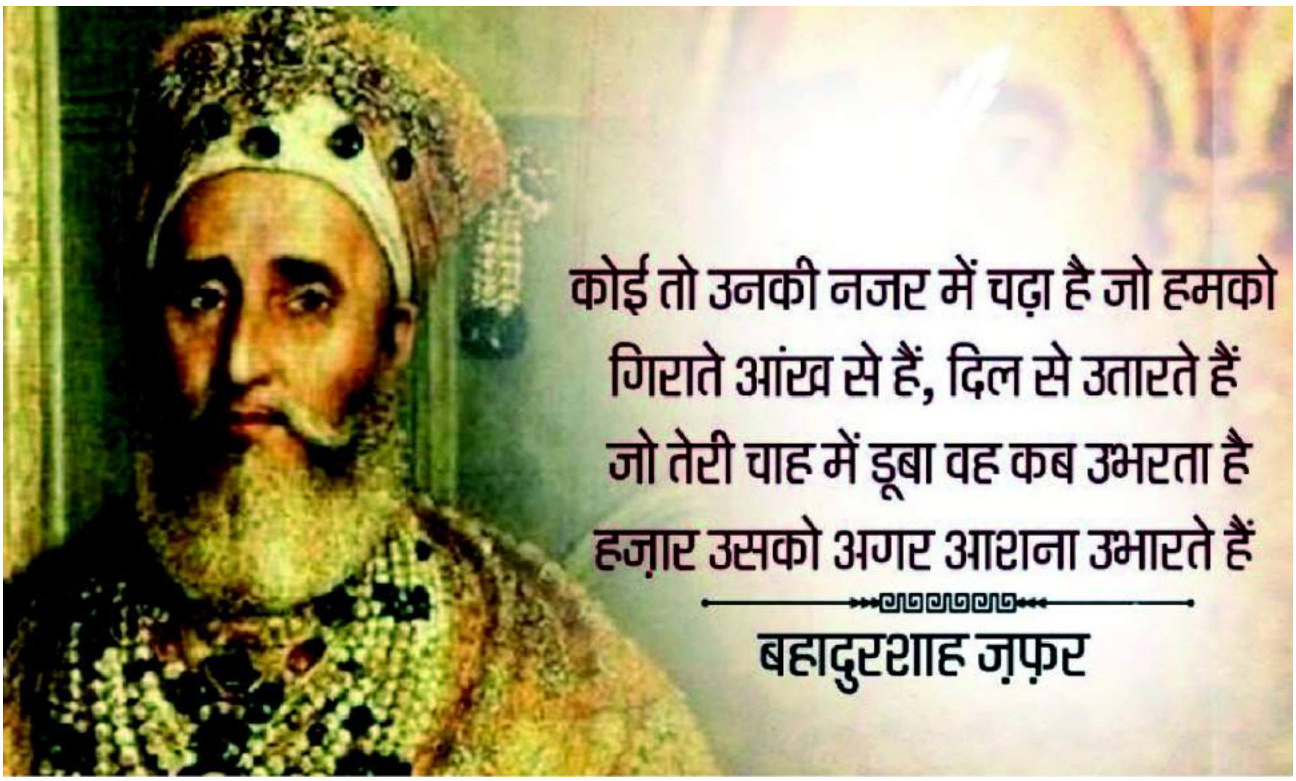

नहीं रह गया था। इसी बीच अफगान अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर हमले शुरू कर दिये। राजपूत तटस्थ होकर बैठ गये। सिख सल्तनत विरोधी बने रहे। रूहेले अब्दाली के साथ हो गये। ऐसे में अपनी रक्षा के लिए बादशाह को मराठों की मदद लेनी पड़ी। बाद में उसे अब्दाली से समझौता भी करना पड़ा लेकिन उत्तर भारत में शक्तिशाली हो चुके मराठे कमजोर मुगल सल्तनत से अपने हित साधने मे लग गये। बादशाह मिलता है।

आलमगीर द्वितीय : अहमदशाह को बंदी बनाकर वजीर-इमाद उल-मुल्क ने दिवंगत बादशाह के पौत्र अहमद अजीजुद्दीन को बंदीगृह से निकालकर आलमगीर द्वितीय नाम से बादशाह बनाया। नये बादशाह की ताजपोशी पर मराठों को सहायता के एवज में 50 लाख रूपये देने और मराठा सत्ता को मान्यता देने के साथ मराठा प्रतिनिधि को 1759 तक शासन किया। वह 55 वर्ष की

हरम में बढ़ती गरीबी से तंग आकर बादशाह ने साहूकारों से कर्ज लिया जिसे वजीर ने सैनिकों के वेतन और प्रशासन व्यय चलाने के लिए रूख लिया। हालत इतनी दयनीय हो गई कि बादशाह के प्रिय मीरबख्शी शमशुद्दौला की जब मौत हुई तब उसके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा नहीं था। घुड़सवार सैनिकों ने अपने घोड़े बेचकर पैसा बटोरा और घरों में बैठ गये। बादशाह की हालत इतनी दयनीय हो गई कि उसके पास

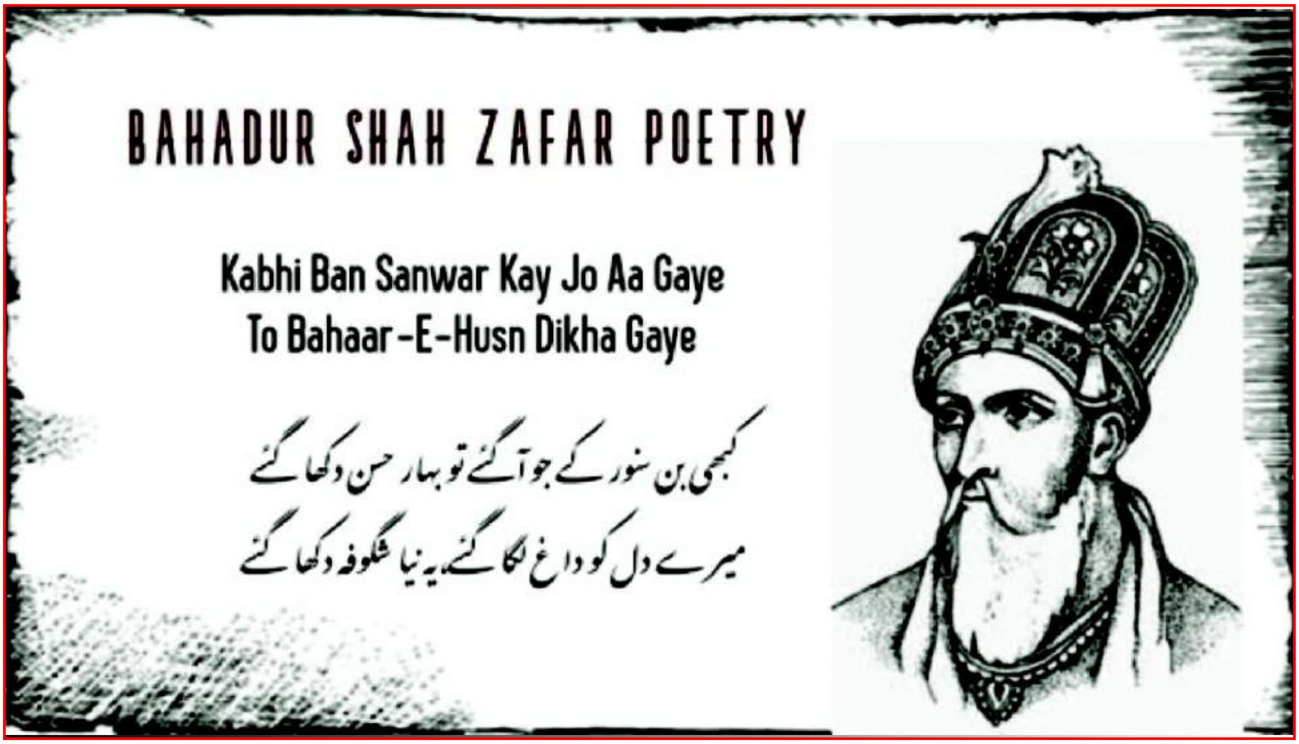

शही सवारी भी नहीं बची थी और दीवान-ए-आम की रौनक इस तरह गिरी कि बादशाह के बैठने के लिए एक मामूली लकड़ी का सिंहासन ही तख्त-ए-ताउस की जगह रख दिया गया था। इसी बीच पंजाब में सूबेदार मुईन-उल-मुल्क की विधवा मुगलानी बेगम ने अहमदशाह अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए उकसाया। अब्दाली के हमलों से बादशाह आलमगीर बुरी तरह टूट गया। उसने मराठों से सहायता की याचना की, फिर अपनी सत्ता बचाने के लिए तरह-तरह के उपाय किये। 29 नवंबर, 1759 को बादशाह फिरोजशाह कोटला के बुर्ज के तहखाने में वजीर इमाद-उल-मुल्क के सैनिकों के हाथों मारा गया। उसका शव यमुना में फेंक दिया गया लेकिन बाद में कुछ सैनिकों ने बादशाह के नग्न शव को नदी से निकालकर मृत्यु के 18 घंटे बाद हुमायूं के मकबरे में मैदान में दफन कर दिया।

शाहजहां तृतीय : आलमगीर की हत्या के बाद औरंगजेब के प्रपौत्र मुही उल मिल्कत को शाहजहां तृतीय के नाम से बादशाह की गद्दी पर बिठाया गया। वजीर ने आलमगीर के बड़े बेटे अली गौहर को निर्दयतापूर्वक हरम के भीतर बंदी जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया। शाहजहां तृतीय नाममात्र का बादशाह था। खाली खजाने के कारण उसे पैसे की तंगी झेलनी पड़ी। हरम के भीतर हिजड़ों, नर्तकियों और विलासप्रिय स्त्रियों के दबाव झेलते-झेलते बादशाह

मानसिक रूप से टूटने लगा। वजीर इमाद-उल-मुल्क ने सल्तनत और लालकिले के भीतर अपना शिकंजा इतनी मजबूती से कस रखा था कि राज परिवार के सदस्य भी भूखों मरने लगे थे। उन्हें वजीर की मेहरबानी से रोटी नसीब होती थी। इसी बीच अली गौहर उर्फ शाहआलम किसी तरह लालकिले से निकलकर दिल्ली से पूर्व की और पलायन कर गया। अहमदशाह अब्दाली ने दिल्ली के आसपास सैनिक घेरा मजबूत कर दिया था। मराठे कई मोर्चो पर अब्दाली से मात खा चुके थे। इसी माहौल में 10 अक्तूबर, 1760 को वजीर और दरबारियों ने बादशाह शाहजहां तृतीय को गद्दी से उतारकर बिहार मे निर्वासित जीवन बिता रहे अली गौहर उर्फ शाहआलम को बादशाह घोषित कर दिया शाह आलम की अनुपस्थिति में उसके बड़े बेटे जमानबख्श को युवराज बनाकर वजीर और दबारियों ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ताच्युत शाहजहां तृतीय लालकिले में बादशाह के हरम के एक कक्ष में चंद दास-दासियों और

हिजड़ों के साथ गरीबी-फटेहाली का जीवन बिताकार कब मर गया, इसका इतिहास में कोई प्रामाणिक जिक्र नहीं है। शाहआलम : शाहआलम द्वितीय दिल्ली लौटकर सत्ता संभाना चाहता था लेकिन उसे पास न तो सैनिक शक्ति थी, न धन शक्ति और न ही उसे जन समर्थन प्राप्त था। रूहेला सरदार नजीबउद्दौला दिल्ली का सर्वोच्च शासक बना बैठा था। अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमाने के लिए निर्वासित बादशाह को दिल्ली लाना चाहते थे लेकिन लखनऊ के नवाब शुजाउद्दौला रूहेलों से झगड़ा मोल नही लेना चाहता था। इसी बीच मराठों में भी दिल्ली में कठपुतली बादशाह की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेने के लिए लालसा जगने लगी। अंततः 12 फरवरी, 1771 को मराठों के साथ बादशाह ने समझौता किया और 6 जनवरी, 1772 को मराठों के संरक्षण में शाहआलम ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहआलम के समय दिल्ली में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। चारों और बदहाली और बदइंतजामी का आलम था। खजाना खाली था, सल्तनत और शाही परिवार पर साहूकारों का कर्ज-बोझ लदा हुआ था। शाहआलम ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया को वकली-ए-तुत्तलिक नियुक्त कर उसे दिल्ली का प्रबंध भार सौंपा। इसी बीच मराठों की अंदरूनी राजनीति के कारण सिंधिया को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा तभी रूहेलों के सरदार गुलाम कादिर ने 30 जुलाई, 1788 को दिल्ली पर हमला बोल दिया। मजबूर बादशाह शाहआलम ने गुलाम कादिर को अमीर-उल-उमरा और मीरबख्शी को पदभार सौंपकर एक तरह से सत्ता उसे भेंट कर दी। इससे मराठे शाहआलम से नाराज हो गये क्योंकि गुलाम कादिर ने आगरा पर कब्जा करने के बाद मराठों के प्रभाव क्षेत्र पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। सिंधिया तो पानीपत की पराजय के बाद से ही नजीबउद्दौला और उसके बेटे गुलाम कादिर के खून का प्यासा बना हुआ था। अपनी बढ़ती सैनिक शक्ति के मद में चूर गुलाम कादिर मुसलमान सरदारों और अमीरों को एकजुट कर नये बादशाह की नियुक्ति की योजना बनाने लगा। 18 जुलाई, 1788 को उसने दिल्ली और लालकिले पर कब्जा कर लिया। बादशाह शाहआलम को गद्दी से उतारकर बंदी बना लिया, साथ ही उसके सभी 19 बच्चों को शाही जेल में डाल दिया। 1 अगस्त, 1788 को उसने दिवंगत बादशाह अहमदशाह के बेटे बिदारबख्त को बादशाह बना दिया।

गुलाम कादिर ने गुप्त शाही कोष को लूट लिया और शाहआलम पर गुप्त खजाने का पता बताने के लिए जोर डालना शुरू किया। नाराज बादशाह ने जब कहा, 'मैने धन अपने पेट में छिपा रखा है' तो गुलाम कादिर ने बादशाह की आंखे फोड़कर उसे अंधा कर दिया। उसने पर्याप्त धन न मिलने की खीज में शाही बेगमों, शाहजादियों का घोर अपमान किया। उनके साथ अपने सैनिको से वीभत्स बलात्कार कराया, शहजादों को पीटा। उन्हें हिजड़ों के साथ नचाया, गवाया और धन की

खोज में शाही महल को जगह-जगह खोद डाला। किसी तरह अपनी दयनीय अवस्था की जानकारी शाहआलम के विश्वस्त दूत मराठों तक पहुंचा सके। खबर सुनकर 2 अक्तूबर, 1788 को महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और गुलाम कादिर को भगा दिया। 16 अक्तूबर, 1788 को मराठों ने शाहआलम को फिर से गद्दी पर बैठाया। बाद में मराठों ने गुलाम कादिर को बंदी बना लिया और उसकी आंखें निकालकर बादशाह को भेज दी। अंधा शाहआलम मराठों की इस बहादुरी से प्रसन्न हुआ। इसी बीज अंग्रेजों ने शाहआलम मराठों की इस बहादुरी से प्रसन्न हुआ। इसी बीच अंग्रेजों ने शाहआलम पर डोरे डालने शुरू कर दिये और महादजी सिंधिया के निधन के बाद उसके उत्तराधिकारी दौलतराव सिंधिया से संधि कर मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया। शाहआलम पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। इसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दिल्ली का संपूर्ण शासन अपने हाथों में ले लिया। बादशाह और हरम की धन की जरूरतो को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने बादशाह को जीवन-निर्वाह के लिए भरपूर धनराशि देनी शुरू कर दी। बाद में स्वेच्छा से शाहआलम ने अपनी बादशाहत दिल्ली के लालकिले के भीतर तक सीमित कर ली और सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों के बादशाह को अपना पेंशनर बना दिया। यद्यपि शाहआलम के समक्ष अंग्रेज शाही शिष्टाचार से पेश आते थे लेकिन किले के बाहर वे स्वेच्छाचारी शासक बन गये थे। 1806 में 86 वर्षीय शाहआलम का निधन हो गया।

अकबरशाह द्वितीय : शाहआलम के बाद अंग्रेजों ने उसे बेटे अकबरशाह द्वितीय को राजसिंहासन पर बिठाया और उसके जरिये भारत में अपनी सत्ता का प्रसार किया। 1835 में तो अंग्रेजों ने दिल्ली में इंग्लैंड के राजा के सिक्के भी चलानेशुरू कर दिये। अकबरशाह की पेंशन 12 से बढ़ाकर 15 लाख रूपये वार्षिक कर दी गई लेकिन शाही खर्च बढ़ता जा रहा था, इस कारण बादशाह को अपने विवेक से खर्च करने के लिए धन की भारी कमी होने लगी। उसने सत्ता पर अंग्रेजों के प्रभाव के खिलाफ इंग्लैंड की सत्ता के समक्ष अपील करने के लिए बंगाल के प्रसिद्ध विद्वान राजा राममोहन राय को अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। नाममात्र के शासक अकबरशाह द्वितीय की 1837 में लालकिले में मृत्यु हो गई, तब अंग्रेजों ने उसे बेटे बहादुरशाह 'जफर' को गद्दी पर बैठाया। बहादुरशाह जफर अंतिम मुगल बादशाह के रूप में इतिहास में जाने जाते हैं। 1857 में भारतीय राजा नवाबों और सैनिकों ने एक बार फिर मुगल सत्ता को बहाल करने के लिए सशस्त्र क्रांति की जिसे अंग्रेजों ने विफल कर दिया। बूढ़े बहादुरशाह ने 20 सितबर, 1857 को अंग्रेज सेनानायक हडसन के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, तब अंग्रेजों ने बादशाह को शाही महल में ही बंदी बनाकर रख दिया। उन पर अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध विद्रोह और सशस्त्र आक्रमण का मुकदमा चलाया गया और उन्हें अपराधी घोषित कर जीवनभर देश निकाले की सजा दे दी गई। अंग्रेजों ने बादशाह बहादुरशाह को भारत से निष्कासित कर रंगून भेज दिया जहां 7 नवंबर, 1862 को उनकी मृत्यु जेल की एक कोठारी में हुई।

30-30 IS BETTER OPTION THAN 20-20

Samta Pathak

Now a days 20 twenty is on its climax. Every one is in the circumference of twenty twenty cricket scenarios. This scenario or you may say the new evaluation of cricket has inspired every one. If we look at future then we see that twenty twenty cricket will disappoint the bowlers and will cast a deep impact on cricket.

So there should be thirty thirty scenario cricket match. Bowlers will be disappointed because in twenty twenty there is long list of batsman to play. Every batsman is seen in the favor of increasing scores by all means. So bowlers are affected. A well known bowler loses its repute as well its standard in cricket of 50-50 as well as in test match. Although the twenty twenty cricket provides the best entertainment but it will decrease the charm of bowling as well as cricket countries will keep on attention to their batsman not on their bowlers. Many cricketers particularly bowlers will face problems during match. In my

opinion if we want to maintain the shape of cricket well then we must immediately leave the twenty twenty cricket scenarios. We must follow a new style of thirty thirty cricket. This new style will bring about new passion to bowlers as well as batsmen will be careful while playing irregular and indiscipline shorts. Batting side team will step in ground with long planning. They will play with great care and hence responsible batting will create new enthusiasm and charm in the cricket. Technical good batsmen will be appeared in front line. All batsmen those who play irresponsible shorts will be disappeared. Spectators will only

see and audience will enjoy the superb cricket. Twenty twenty has changed the shape of cricket. It is only batsman side cricket. If there will be thirty thirty scenario cricket then there will be fifty chances of cricket having both sides bat and ball. When there will be one sided cricket then image of cricket will be washed out. So to maintain the shape of cricket we must back up thirty thirty so we may enjoy the best cricket. in twenty twenty cricket we could not see the charm of bowling. Every bowler was beaten by batsman in inhuman manner.There was no respect of bowler.. we must watch equally level cricket. In thirty thirty overs batsmen will have to think several times to play irresponsible shorts. So in the same passion bowlers will have a sigh of relief and they will have a chance to perform well. In short there are many drawbacks of twenty twenty cricket and one of them has been discussed. I think you people will have to think over it.

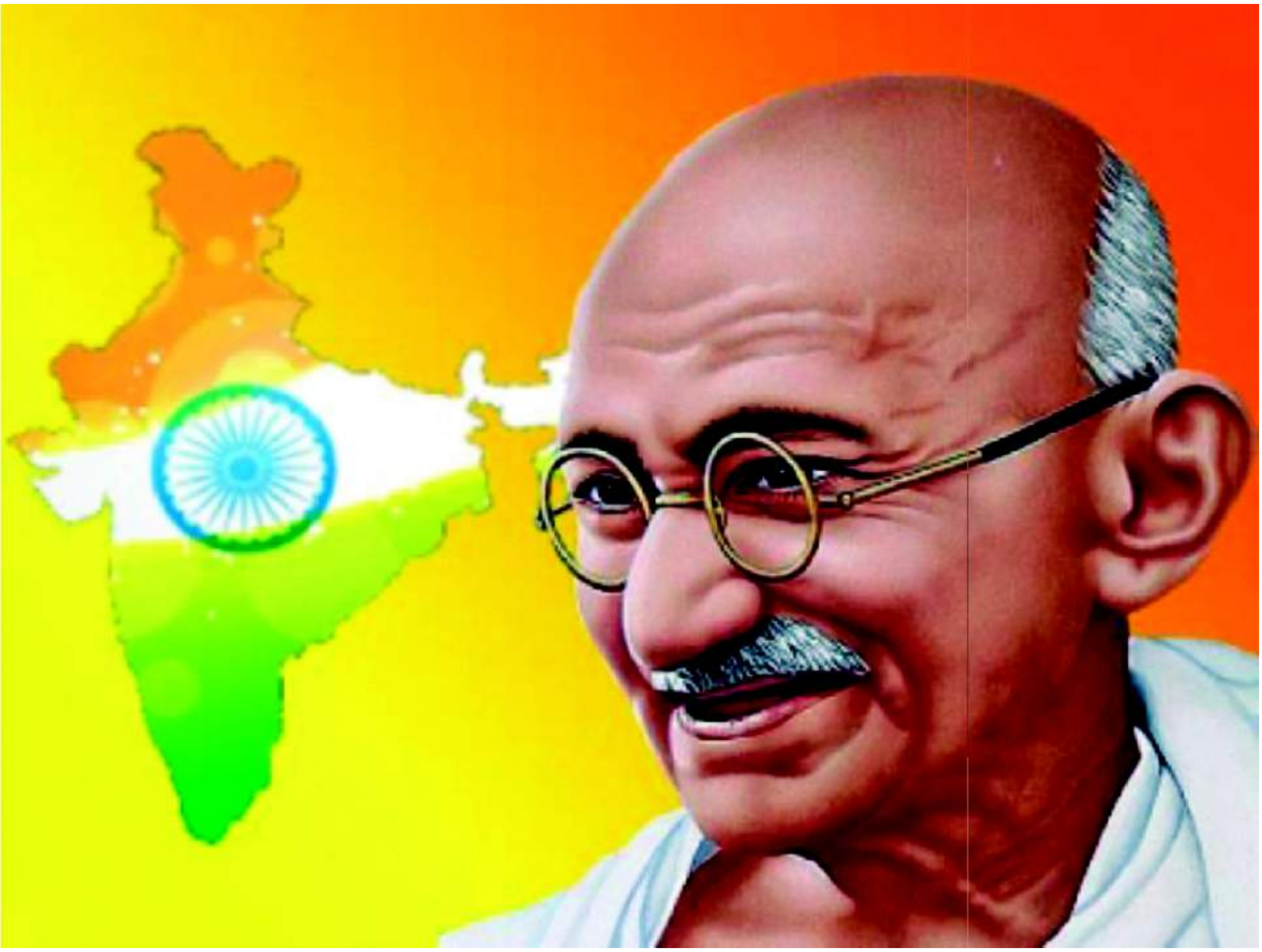

PEACEMAKER HERO MOHANDAS K. GANDHI

Shaifali Dubey

In the early 1600s, sailors from Great Britain made their way to India. At that time, India was a country rich in traditions and culture thousands of years old. The British Empire took control of the government of India and forever changed the face of that country. Ancient traditions and religions were thrown out, made illegal by ruthless British generals eager to make India another England. As you can well imagine, the native people of India suffered greatly, seeing their way of life trampled under the British desire to "civilize" their country.

For the longest time, nobody in India successfully fought back against the British and the oppression they brought with them. This all changed when a

small man, born in the ancient city of Porbandar in 1869, stood up and said "Enough!" This man became known the world over as Gandhi, the mahatma or "Great Soul" of India. Mohandas Karamchand Gandhi's early years showed little sign of the great life he would go on to live. He went to school, was married and later became a rather unsuccessful, terribly shy lawyer. All of this changed, however, one fateful day when Gandhi was denied a seat on a stagecoach in South Africa. The racist driver had made him sit outside in the hot sun on a long trip to Pretoria, simply because he wasn't white. Gandhi, until now too shy to even speak in front of a judge, sued the railroad company and won. From that point on, Gandhi became the number-one spokesman for all powerless non-whites the world over. After 20 years of aiding his fellow Indians in South Africa, Gandhi returned to India and picked up the fight against British oppression. Instead of encouraging native born Indians to take up arms and force the British colonists out of their country, Gandhi created a policy of non-violent protest. "Non-violence, " he said, "is a weapon for the brave." For 20 years, non-violent protests, marches and strikes by the Indians wore down British resistance. Confronted by a slight man wearing only a plain cloth and accompanied by millions of followers armed not with weapons but love and truth, the British government in 1946 finally gave India its long-held dream of independence. The fight for India's freedom had been won without a battle having ever been fought.

Sadly, two years after his great victory, Gandhi was shot and killed by an assassin's bullet. But Gandhi's legacy lived on after his death, showing the world that one can be a hero and accomplish great things without guns or swords or hatred. As Gandhi once said, "It is non-violence only when we love those that hate us. I know how difficult it is to follow this grand law of love, but are not all great and good things difficult to do? Love of the hater is the most difficult of all. But by the grace of God even this most difficult thing becomes easy to accomplish if we want to."

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

SAWARNA COSMETICS

SHOP NO. 101/152, NEW MARKET,
BHOPAL, M.P. 462016

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मध्यप्रदेश सरकार अग्रसर

राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर देकर और उन्हें हर क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के प्रयासों से आज मध्यप्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के जीवन में बदलाव आ रहा है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना

उद्देश्य- बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।

- अब तक इस योजना के अंतर्गत **39.50 लाख** से अधिक बालिकाएं लाभान्वित।
- शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 में कक्षा 06, 09, 11 और 12 में प्रवेश लेने वाली कुल **2,34,760 बालिकाओं को छात्रवृत्ति वितरित।**

वन स्टॉप सेंटर

सखी वन स्टॉप सेंटर

उद्देश्य- हिंसा पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को आश्रय, परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता एवं पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं।

- वन स्टॉप सेंटर की सहायता से पिछले 3 वर्षों में 39 हजार बालिकाएं एवं महिलाएं लाभांवित हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अब तक **12 हजार बालिकाएं एवं महिलाएं लाभांवित।**
- 39 वन स्टॉप सेंटर्स को आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

उद्देश्य- विपत्तिग्रस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़कर स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार के भरण पोषण में मदद करना।

- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में अब तक **276 महिलाओं** को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण हेतु चयनित कर शासकीय/ अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उदिता योजना

उद्देश्य- महिलाओं में माहवारी स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने, समुचित माहवारी प्रबंधन के बारे में जागरूकता तथा संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया।

- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत उदिता कॉर्नर के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए जिलों में तेजस्वनी, नाबार्ड एवं एस.आर.एल.एम.के स्वसहायता समूहों से अनुबंध किए जा रहे हैं।
- प्रदेश के कई जिलों में स्वसहायता समूह/ फेडरेशन की महिलाओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्थापित उदिता कॉर्नर पर स्वनिर्मित सेनेटरी नैपकिन की सप्लाई।
- माहवारी स्वच्छता एवं प्रबंधन पर अब तक प्रदेश में **1.25 लाख महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण।**

शौर्या दल

उद्देश्य- आदिवासी, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति अनुकूल वातावरण का निर्माण कर उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना।

- महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति समाज में नकारात्मक सोच, कुप्रथा एवं उनके प्रति भेदभाव में परिवर्तन लाना एवं एक दल संगठित कर महिला शक्ति का विस्तार करना।
- प्रदेश में कुल **17,20,026 बालिकाएं** एवं **महिलाएं** शौर्या दल की सदस्य हैं जिनमें से **7,29,320 बालिकाएं** एवं **9,90,706 महिला** सदस्य है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

उद्देश्य- शिशु लिंगानुपात एवं भविष्य में जेंडर असंतुलन की विषम स्थिति में सुधार लाना।

- वर्तमान में प्रदेश के 42 जिलों में इस योजना का संचालन।
- जन्म में लिंगानुपात में सुधार वाले जिले हैं: अनूपपुर, बड़वानी, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास, दमोह, धार, ग्वालियर, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, नरसिंहपुर, पन्ना, राजगढ़, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिंगरौली, शिवपुरी, टीकमगढ़ एवं उमरिया।

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

योजना का लाभ लेने और अधिक जानकारी के लिए

अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र/ बाल विकास परियोजना अधिकारी/ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास से संपर्क करें।

D-16046/21